RNI NO. CHHHIN/2022/83778

न्यूज रूटीन

मासिक, बलौदाबाजार से प्रकाशित

जरूरी नहीं कि मिठाई खिलाकर ही दूसरों का मुंह मीठा करें, आप मीठा बोलकर भी लोगों को खुशियां दे सकते हैं!

वर्ष : 03 अंक : 06 | मासिक, बलौदाबाजार, जून 2024 | E-mail: newsroutine6@gmail.com | पृष्ठ : 16 | मूल्य : 15 रू.

छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में बीजेपी का डंका

एससी/एसटी के लिए आरक्षित सभी 5 लोकसभा सीटों पर जीत

छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने 11 में से 10 सीटों पर कब्जा जमाया. खास बात यह रही कि छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सभी पांच लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है. बीजेपी ने बस्तर सीट भी कांग्रेस से छीन ली है.

छत्तीसगढ़ की कुल 11 लोकसभा सीटों में से बस्तर, कांकेर, रायगढ़ और सरगुजा एसटी वर्ग के लिए और जांजगीर-चांपा एससी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है. भाजपा ने 11 में से 10 सीटें जीतीं और कांग्रेस एक सीट बरकरार रखने में सफल रही.

बस्तर लोकसभा क्षेत्र में बड़ा उलटफेर

आरक्षित सीटों में से बस्तर लोकसभा क्षेत्र में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला. बस्तर में भाजपा के महेश कश्यप ने कांग्रेस के प्रभावशाली आदिवासी नेता और मौजूदा विधायक कवासी लखमा के खिलाफ 55,245 वोटों से जीत हासिल की. साल 2019 में कांग्रेस ने जो दो सीटें जीतीं, उनमें बस्तर भी शामिल थी.

कांग्रेस ने इस बार अपने मौजूदा सांसद और प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दीपक बैज को हटा दिया. कांग्रेस ने लखमा को मैदान में उतारा, जो छत्तीसगढ़ की पिछली कांग्रेस सरकार में मंत्री थे.

सरगुजा में भाजपा उम्मीदवार चिंतामणि महाराज ने कांग्रेस के शशि सिंह के खिलाफ 64,822 वोटों के अंतर से जीत हासिल की. चिंतामणि महाराज पिछले साल के राज्य विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हो गए थे.

2.4 लाख वोट के अंतर से जीते राठिया

रायगढ़ में, भाजपा के राधेश्याम राठिया ने कांग्रेस उम्मीदवार डॉ. मेनका देवी सिंह के खिलाफ 2,40,391 वोटों के अंतर से जीत हासिल की, जो सारंगढ़ के पूर्व शाही परिवार से हैं. कांकेर में बीजेपी के भोजराज नाग ने कांग्रेस प्रत्याशी बीरेश ठाकुर को 1884 वोटों से हराया. 2019 में भी ठाकुर कांकेर से 6,914 वोटों के मामूली अंतर से हार गए थे.

भारतीय जनता पार्टी ने 11 में से 10 सीटों पर कब्जा जमाया.

एससी आरक्षित अकेली सीट पर भी हारी कांग्रेस

एकमात्र एससी-आरक्षित जांजगीर-चांपा सीट पर, भाजपा के कमलेश जांगड़े ने अपने कांग्रेस प्रतिद्वंद्वी और पूर्व राज्य मंत्री शिवकुमार डहरिया को 60,000 वोटों के अंतर से हराया. साल 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर राज्य बनने के बाद से 2019 तक सभी आरक्षित लोकसभा सीटें कांग्रेस की पकड़ से बाहर थीं. भाजपा ने राज्य में 2004, 2009 और 2014 के लोकसभा चुनावों में 11 में से 10 सीटें जीती थीं. 2019 में कांग्रेस ने बस्तर समेत दो सीटें जीतीं.

छत्तीसगढ़ की आदिवासी सीटों का इतिहास

छत्तीसगढ़ के आदिवासी सीटों पर लोकसभा का चुनावी परिणाम दिलचस्प रहा. बीजेपी ने प्रदेश के सभी आदिवासी सीटों पर जीत दर्ज की है, जिनमें सरगुजा, रायगढ़, कांकेर, जांजगीर-चांपा और बस्तर शामिल हैं. सरगुजा सीट से चिंतामणि महाराज, कांकेर से भोजराज नाग, बस्तर से दिनेश कश्यप, जांजगीर चांपा से कमलेश जांगड़े और रायगढ़ से राधेश्याम राठिया ने जीत दर्ज किया है. सरगुजा लोकसभा सीट पर साल 2004 से भाजपा का कब्जा है. वहीं रायगढ़ में बीजेपी 1999 से अजेय रही है. जांजगीर चांपा में 2004 से बीजेपी जीतते आ रही है. कांकेर सीट 1999 से भाजपा के पास रही है. बस्तर लोकसभा सीट पर 1999 से 2014 तक भाजपा ने जीत दर्ज की. हालांकि, 2019 में कांग्रेस के दीपक बैज ने यहां से जीत दर्ज किया. लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर से यह सीट बीजेपी के खाते में चली गई है.

आदिवासी सीएम चेहरे का मिला फायदा

विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा की बड़ी जीत के बाद प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री का चेहरा प्रस्तुत किया गया. बीजेपी ने आदिवासी समाज से आने वाले विष्णुदेव साय को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया. इसी आदिवासी चेहरे का असर अब आदिवासी लोकसभा सीटों के परिणामों में देखने को मिल रहा है.

जनदर्शन में देखने को मिली मुख्यमंत्री साय की संवेदनशीलता

अनवरत पांच घंटे आम लोगों से मिले और उनकी समस्याएं सुनीं

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का राज्य की जनता को स्वच्छ, पारदर्शी, संवेदनशील एवं प्रभावी प्रशासन मुहैया कराने का संकल्प एक-एक कर अमल में दिखाई देने लगा है। सत्ता की बागड़ोर सम्भालने के बाद से ही शासन-प्रशासन को जनता के करीब लाने की मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की इच्छा आज जनदर्शन में पूरी होती दिखी। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राज्य में जनसमस्याओं की सुनवाई के लिए नये सिरे से जनदर्शन कार्यक्रम की शुरूआत की है। जनदर्शन का यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में 27 जून गुरूवार को आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने जनदर्शन कार्यक्रम में प्रदेश के दूर-दराज से आए हजारों लोगों से एक-एक कर मुलाकात की। बड़े ही अपनत्व भाव से उन्होंने आम जनमानस की समस्याएं और उनकी अपेक्षाएं सुनी और विभागीय अधिकारियों को प्राप्त शिकायतों एवं आवेदनों को तत्परता से निपटाने के निर्देश दिए।

आज 27 जून को मुख्यमंत्री जनदर्शन का पहला कार्यक्रम हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोग अपने आवेदनों और समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री श्री साय से मिलने रायपुर स्थित उनके कार्यालय पहुंचे थे। जनदर्शन का समय पूर्वान्ह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक निर्धारित था, परन्तु कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनसामान्य की मौजूदगी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने न सिर्फ जनदर्शन कार्यक्रम की निर्धारित समयावधि को बढ़ाया, बल्कि स्वयं कार्यक्रम में यह बात कही कि लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहां आए प्रत्येक व्यक्ति से वह मिलेंगे और उनकी समस्याओं और अपेक्षाओं को सुनेंगे। यही वजह है कि मुख्यमंत्री जनदर्शन का यह कार्यक्रम पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 4 बजे तक अनवरत पांच घंटे चला। मुख्यमंत्री श्री साय इस दौरान सभी आयु वर्ग के लोगों से एक-एक कर उनकी समस्याएं सुनी।

मुख्यमंत्री श्री साय का लोगों के प्रति अपनेपन का भाव एवं संवेदनशीलता ने जनमानस की शासन-प्रशासन से दूरी को मिटा दिया है। जनदर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एक ओर जहां विभिन्न बीमारियों से पीड़ित लोगों के समुचित इलाज और मदद के लिए अधिकारियों को निर्देश देते दिखे, वहीं दिव्यांग और निशक्तजनों के बीच पहुंचकर न सिर्फ उनकी समस्याएं सुनी, बल्कि उन्हें आवश्यक उपकरण, ट्राईसायकल आदि की सौगातें दीं। मुख्यमंत्री इस दौरान उच्च शिक्षा एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए इच्छुक युवाओं के लिए भी आवश्यक प्रबंध करने के लिए तत्परता से अधिकारियों को निर्देशित करते दिखे।

जनदर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें अपनी समस्याएं बताने को लेकर लोग काफी उत्साहित थे। भारी उमस और गर्मी के बावजूद भी जनदर्शन स्थल लोगों से खचाखच भरा था। मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी समस्याओं की जानकारी देने के लिए लोग अपनी बारी का इंतजार करते दिखे।

नशे के विरूद्ध अभियान के लिए राजनांदगांव जिला राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित

- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दिया सम्मान, मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने दी बधाई
- मुख्यमंत्री साय के निर्देश पर प्रदेशभर में 'एक युद्ध नशे के विरूद्ध अभियान' को चलाया गया

राजनांदगांव। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे नशा विरोधी अभियान के प्रभावी जमीनी क्रियान्वयन का असर दिखने लगा है।

प्रदेश में 'एक युद्ध नशे के विरूद्ध अभियान' के शानदार संचालन के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने उल्लेखनीय कार्य के लिए राजनांदगांव जिले को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने इसके लिए जिला प्रशासन राजनांदगांव को बधाई दी है। साथ ही उन्होंने नशे के विरूद्ध सतत् अभियान चलाते रहने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि बच्चों में नशे की आदत को रोकने के लिए प्रभावी अभियान निरंतर चलाते रहें।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बच्चों द्वारा ड्रग्स एवं स्वापक ओषधियों के प्रयोग तथा बच्चों के अवैध तस्करी की प्रभावी रोकथाम हेतु 'एक युद्ध नशे के विरुद्ध' पर जॉइंट एक्शन प्लान के क्रियान्वयन के निर्देश थे। मुख्यमंत्री श्री साय ने महिला एवं बाल विकास विभाग को जॉइंट एक्शन प्लान के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए थे। इसके परिपालन में विभाग द्वारा इस अभियान को प्रभावी संचालन हेतु सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश जारी किए गए। विभिन्न स्टेक होल्डर्स के लिए प्रशिक्षण आयोजित किये गए। नियमित मॉनिटरिंग की गई। राज्य के सभी जिलों में इस अभियान का संचालन जिला प्रशासन एवं जिला बाल संरक्षण ईकाई द्वारा विभिन्न विभागों के समन्वय से किया गया।

सभी जिलों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई जिसमें महिला बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग स्वास्थ्य विभाग ,उच्च शिक्षा विभाग समाज कल्याण और औषध नियंत्रक विभाग आदि सभी की सहभागिता कर समन्वय समिति का गठन किया गया। जिलों में इस अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रचार प्रसार किया गया।बच्चों को नशे का आदि बनाने एवं नशे के व्यापार से जोड़ने के दोषियों के विरुद्ध किशोर न्याय अधिनियम की धारा 77 एवं 78 के प्रावधान अनुसार कार्यवाही के निर्देश दिए गए।

राज्य स्तर से जारी निर्देश एवं एक्शन प्लान के अनुसार सभी जिलों में कार्य हुए। राजनांदगांव जिले में सबसे उल्लेखनीय कार्य किया गया। ज़िलें के सभी स्कूलों में प्रहरी क्लब बनाए गए। नशे के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन शासकीय एवं निजी स्कूल में बनाए गए प्रहरी क्लब के माध्यम से किया गया। जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा सभी स्कूलों के आसपास शराब दुकानों को हटाया गया है। औषधि प्रशासन विभाग द्वारा एक्ट के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की गई एवम लगातार चालान की कार्यवाही की गई । ज़िलें में एक लाख से अधिक की राशि का चालान काटा गया। दुकानों से जहां बच्चों को नशे तंबाकू का पदार्थ दिया जा रहा था या दुकानें स्कूल के पास संचालित थे। उन पर कार्रवाई की गई जिले में कलेक्टर द्वारा सभी दवाई दुकानों में सीसीटीवी लगाने का आदेश जारी किया गए तथा लगातार दुकानों में सीसीटीवी के माध्यम से जिले में पुलिस विभाग एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की गई।

नगरीय निकायों में प्री-ऑडिट के निर्देश

- चालू वित्तीय वर्ष के प्री-ऑडिट के साथ ही पिछले चार वर्षों की लंबित अवधि का भी होगा पोस्ट ऑडिट
- नगरीय निकायों में कड़े वित्तीय अनुशासन लागू करने में मिलेगी मदद, भुगतान संबंधी सभी नियमों का पालन होगा सुनिश्चित

रायपुर। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने नगरीय निकायों में वित्तीय अनुशासन में कसावट लाने सभी आय एवं व्ययों के प्री-ऑडिट के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पिछली सरकार द्वारा ऑडिट प्रक्रिया बंद कर दिए जाने के कारण ऑडिट से रह गए विगत चार वर्षों की नस्तियों के पोस्ट ऑडिट कराने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदेश की सभी 184 नगरीय निकायों के साथ ही नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के यांत्रिकी प्रकोष्ठ तथा राज्य शहरी विकास अभिकरण का भी ऑडिट कराने को कहा है।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने नगरीय निकायों में कड़े वित्तीय अनुशासन के लिए प्री-अंकेक्षण-सह-आंतरिक अंकेक्षण की प्रक्रिया को पुनः प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। उनके निर्देश पर सभी 184 नगरीय निकायों तथा दो राज्य कार्यालयों, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के यांत्रिकी प्रकोष्ठ और सूडा को भी प्री-अंकेक्षण-सह-आंतरिक अंकेक्षण एवं वैधानिक दायित्व के परिपालन के दायरे में लाते हुए सूडा द्वारा कार्ययोजना तैयार की जा रही है।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने प्री-अंकेक्षण-सह-आंतरिक अंकेक्षण की जरूरत को रेखांकित करते हुए कहा कि नगरीय निकायों में अंकेक्षण प्रारंभ होने से सभी भुगतान नस्तियों का परीक्षण प्री-ऑडिट के माध्यम से सीए फर्म द्वारा किया जाएगा। इससे भुगतान संबंधी सभी नियमों का परिपालन सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि अंकेक्षण प्रारंभ होने के बाद पूर्ववर्ती सरकार द्वारा ऑडिट बंद किए जाने के बाद की समस्त नस्तियों का नवीन सीए फर्म की नियुक्ति के बाद पोस्ट ऑडिट कराया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि नगरीय निकायों में वित्तीय अनुशासन की अनिवार्यता एवं महत्ता को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ में प्रथम बार प्री-अंकेक्षण-सह-आंतरिक अंकेक्षण का कार्य वर्ष 2015-16 से प्रारंभ किया गया था। नगर पालिक निगम अधिनियम-1956, नगर पालिका अधिनियम-1961 एवं संबंधित नियम, कार्य विभाग मैन्युअल, भण्डार क्रय नियम तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत आने वाले निकायों में आंतरिक अंकेक्षण के लिए पांच समूहों में पृथक-पृथक अनुभवी चार्टर्ड एकाउन्टेंट एजेंसीज को आंतरिक अंकेक्षक नियुक्त किया गया था।

निकायों में आंतरिक अंकेक्षण से हुए थे ये लाभ

प्रदेश के नगरीय निकायों में पूर्व में कराए गए आंतरिक अंकेक्षण से कड़े वित्तीय अनुशासन को लागू करने में बहुत मदद मिली थी। प्री-ऑडिट कराए जाने से निकायों में बजट के मद परिवर्तन को रोका गया। विभिन्न निर्माण एवं प्रदाय कार्यों से संबंधित भुगतान पर नियंत्रण होने से निकायों में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से 100 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई। सेट-अप के अनुसार स्थापना व्यय के भुगतान की अनुशंसा से अतिरिक्त व्यय पर नियंत्रण हुआ। साथ ही वैधानिक दायित्वों के समय पर निराकरण एवं भुगतान में सुधार के कारण नगरीय निकायों पर लगने वाले शास्ति में कमी आई थी।

सारंगढ़ ब्लॉक में पेंशन योजनाओं के हितग्राहियों का होगा सत्यापन और केवाईसी अपडेट

सारंगढ़ बिलाईगढ़। समाज कल्याण संचालनालय से जारी पत्र के क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर श्री धर्मेश साहू ने सारंगढ़ ब्लॉक में पेंशन योजनाओं के हितग्राहियों का पात्र अपात्र के संबंध में जांच करने के लिए पत्र जारी किया है, जिसके पालन में 6 योजनाओं के हितग्राहियों का सत्यापन एवं केवाईसी अपडेट के लिए दल को उप संचालक विनय तिवारी ने जनपद पंचायत सारंगढ़ के सभाकक्ष में प्रशिक्षण प्रदान किया। ये दल 1 जुलाई से 5 जुलाई तक अपने क्षेत्र में कार्य करेंगे। ये हितग्राहियों के मूल दस्तावेज से मिलान कर पात्र और अपात्र के संबंध में रिपोर्ट सीईओ जनपद पंचायत सारंगढ़ को प्रस्तुत करेंगे।

समाज कल्याण विभाग की योजना सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत 6 पेंशन योजनाएं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्तजन पेंशन योजना सुखद सहारा पेंशन योजना एवं मुख्यमंत्री पेंशन योजना के हितग्राहियों का सत्यापन एवं केवाईसी अपडेट कार्य के सुचारू संपादन हेतु सारंगढ़ विकासखंड के ग्रामवार समस्त नामांकित सत्यापनकर्ता अधिकारी प्रधान पाठक, शिक्षक, शिक्षिका, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मितानिन का एक दल बनाया गया है।

दिव्यांगों के लिए हर संभव मदद की जाएगी- साय

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज यहां जैन दादा बाडी एमजी रोड में नारायण सेवा संस्थान द्वारा आयोजित विशाल नि:शुल्क नारायण लिम्ब एवं कैलिपर्स फिटमेंट शिविर में शामिल हुए। संस्थान ने इस शिविर में छत्तीसगढ़ प्रदेश के रायपुर तथा विभिन्न जिलों से आए 750 से ज्यादा दिव्यांगों को अपर-लोवर लिंब और केलिपर्स लगाकर उनकी रुकी जिंदगी को फिर से शुरू कर दी। इन दिव्यांगों और परिजनों की खुशी हर किसी के मन को छूने वाली थी। आज एक ही दिन में एक ही जगह पर 750 से ज्यादा दिव्यांग नारायण लिम्ब पहनकर मुस्कुराते हुए चले। जो वर्षों पहले किसी दुर्घटना में अपने हाथ-पैर गंवाने से चलने-फिरने में असमर्थ हो चुके थे। जिसके चलते इनकी जिंदगी रुक सी गई थी। इन्हें आज लोवर लिंब, अपर लिंब, मल्टिपल लिंब और केलिपर्स लगाए गए।

नारायण सेवा संस्थान के शिविर में 750 दिव्यांगों को लगे नारायण लिम्ब

शिविर का उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय तथा अन्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री टंकराम वर्मा, विधायक श्री पुरंदर मिश्रा, श्री मोती लाल साहू और श्री अनुज शर्मा, दिव्यांगों, उनके परिजनों सहित कई सम्मानीय दानी जन मौजूद थे।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने मुख्य अतिथि की आसंदी से कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि राजस्थान से चलकर छत्तीसगढ़ के दिव्यांगों की मदद के लिए आगे आयी इस संस्थान की भावना का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने संस्थान के संस्थापक कैलाश जी मानव व अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल का इस भव्य मानव यज्ञ के लिए आभार प्रकट करते हुए राज्य सरकार की ओर से संस्थान को दिव्यांगों के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया।

कार्यक्रम के प्रारम्भ में संस्थान द्वारा मुख्य अतिथि सहित सभी अतिथियों का मेवाड़ी परंपरा से सत्कार किया गया। संस्थान के प्रतिनिधियों द्वारा मानवता की सेवा के अपनी 39 वर्षीय यात्रा की जानकारी देते हुए आगामी 5 वर्ष का विजन प्रस्तुत किया गया। संस्थान द्वारा बताया गया कि हमने दिव्यांगजनों को उनके घरों के पास ही लाभान्वित करने की सोच को साकार करते हुए 7 अप्रैल को रायपुर में कैंप लगाया था। आज उन्हें जरूरी उपकरण मुख्यमंत्री जी के हाथों उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

नारायण सेवा संस्था के अध्यक्ष श्री प्रशांत अग्रवाल ने संकल्प रखा की वे आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ के दिव्यांगों को लाभान्वित करने के लिए रायपुर में केंद्र संचालित करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि नारायण सेवा संस्थान द्वारा केंद्र स्थापना के लिए उन्हें हर संभव मदद दी जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ के रायपुर तथा विभिन्न जिले से आए दिव्यांगों जिनके कृत्रिम हाथ पैर लगे उनसे मिलकर उन्हें शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिव्यांगों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।

सेवानिवृत पर बीईओ कार्यालय बरमकेला ने जारी किया 6 शिक्षकों का पीपीओ

सारंगढ़ बिलाईगढ़। कलेक्टर श्री धर्मेश साहू के निर्देश पर बरमकेला विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा लगातार दूसरे माह जून में भी 6 शिक्षकों को सेवानिवृत होने पर उनका पेंशन भुगतान का आदेश पत्र (पीपीओ) जारी किया गया है। विगत माह मई में 5 शिक्षकों को पीपीओ जारी किया गया था। विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बरमकेला और शाखा प्रभारी ने सकारात्मक और सार्थक प्रयास करते हुए सेवानिवृत्ति तिथि के दो दिवस पूर्व छ कर्मचारियों का पीपीओ जारी करवा कर एक पारदर्शी पहल किया है।

विकासखंड शिक्षा अधिकारी नरेंद्र जांगड़े ने बताया कि 30 जून को अधिवार्षिकी पूर्ण करने वाले छः प्रधान पाठकों क्रमश ब्रजमोहन नायक,टीकाराम नायक,भुवनेश्वर प्रधान, नोहन सिंह पटेल हेमलाल और कंवल सिंह नायक को उनके पेंशन सहित अन्य स्वत्वों की भुगतान समय सीमा में हो इसके लिए पीपीओ जारी किया गया है। शाखा प्रभारी प्रदीप पटेल ने इस संबंध मे बताया कि पेंशन का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी वाला कार्य है। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को सभी प्रकार की भुगतान तय सीमा मे हो, इसके लिए दो तीन माह पहले से कार्य प्रारंभ करना पड़ता है। सभी जानकारी को गहनता एवम सूक्ष्मता से परीक्षण किया जाकर वरिष्ठ कार्यालय एवम ट्रेजरी भेजा जाता है। जहां तमाम जानकारी और बिलों की क्रॉस वेरीफिकेशन होने के बाद पीपीओ जारी किया जाता है। प्रदीप पटेल ने आगे बताया कि सेवानिवृत तिथि से दो दिन पूर्व छ प्रधान पाठकों का पीपीओ जारी होना विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय की पारदर्शी पहल और कार्यों के प्रति जवाबदेही को दर्शाता है। नि:संदेह सेवानिवृति तिथि से दो दिवस पीपीओ जारी होना बीईओ और शाखा प्रभारी प्रदीप पटेल की सजगता और संवेदनशीलता को दर्शाता है। विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बरमकेला का यह प्रयास कार्यालय की विश्वसनीयता और शिक्षकों की विभागीय कार्यों को समय सीमा मे पूर्ण करने की प्रतिबद्धता को इंगित करता है। समय पूर्व पीपीओ जारी होना शाखा प्रभारी प्रदीप पटेल की सजगता और सार्थक प्रयास का ही परिणाम है।

सभी विभाग को सेवानिवृत पर पीपीओ जारी करने की जरुरत

एक लंबी सेवा अवधि के उपरांत अधिवार्षिकी पूर्ण (सेवानिवृत) करने वाले अधिकारी,कर्मचारियों का समाज, देश और प्रदेश के समग्र विकास में अपना अमूल्य योगदान देते हैं। उन्हे मिलने वाली पेंशन उनके द्वारा प्रदेश और समाज के विकास और कल्याण के लिए किए गए सकारात्मक और सार्थक कार्यों का प्रतिफल है। विषम परिस्थितियों मे भी कर्तव्यनिष्ठ होकर अपनी दायित्वों का सफलता पूर्वक निर्वहन करते हुए विकास के मार्ग को प्रशस्त करने वाले ऐसे सेवानिवृत होने वाले अधिकारी कर्मचारियों को बिना किसी परेशानी के विभाग के तमाम स्वत्वो का भुगतान समयानुसार हो, यह सभी विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए।

बलौदाबाजार में क्षतिग्रस्त वाहनों के बीमा क्लेम जल्द से जल्द सेटलमेंट करने परिवहन सचिव के निर्देश

रायपुर। बलौदाबाजार कलेक्टोरेट में हुए आगजनी की घटना में क्षतिग्रस्त हुए वाहनों के बीमा क्लेम का त्वरित निराकरण जल्द किया जाएगा। परिवहन विभाग के सचिव श्री एस प्रकाश ने मंत्रालय महानदी भवन रायपुर में समस्त बीमा कम्पनियों के अधिकारियों की बैठक में निर्देशित किया कि बीमा क्लेम और क्लेम सेटलमेंट की कार्यवाही जल्द से जल्द पूर्ण की जाए।

बलौदा बाजार कलेक्टोरेट में हुई आगजनी की घटना में फस्ट पार्टी बीमा कराए गए वाहनों की संख्या 56. थर्ड पार्टी बीमा कराए गए वाहनों की संख्या 92 तथा बिना बीमा कराए गए वाहनों की संख्या 92 कुल 240 क्षतिग्रस्त वाहनों की संख्या में से मुख्य रूप से ओडी बीमा क्लेम प्रकरणों पर विशेष रूप से चर्चा की गई। वर्तमान में कुल 12 ओडी बीमा क्लेम प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। अनावश्यक लंबित बीमा प्रकरणों पर परिवहन सचिव द्वारा नाराजगी जाहिर करते हुए 10 दिनों में निराकरण करने का निर्देश दिया गया एवं जिला परिवहन अधिकारी, बलौदा बाजार को निर्देशित किया गया कि किसी प्रकार की समस्या का त्वरित निराकरण एवं कार्यवाही सुनिश्चित करें।

नेशनल लोक अदालत, दोनों पक्ष सहमत हो तो राजीनामा के मुकदमा का 13 जुलाई को करा सकते हैं रफादफा

सारंगढ़ बिलाईगढ़। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली द्वारा 13 जुलाई 2024 को सभी मामलों पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना निर्धारित किया है, जिसमें सिविल और राजस्व न्यायालयों में लम्बित राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, चेक बाउन्स के मामले, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा एवं व्यवहार प्रकृति के मामलों, जिसमें निष्पादन प्रकरण भी सम्मिलित हैं, के अलावा, भूमि अधिग्रहण, आबकारी, श्रम, विद्युत, टेलीफोन सम्बन्धी प्रकरण बैंक रिकव्हरी के राजीनामा हेतु रखे जायेंगें, जिसमें मुकदमा पूर्व वाद भी लोक अदालत में प्रस्तुत कर राजीनामा के द्वारा निराकृत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त धारा 188 भा.द.सं. एवं कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 एवं अन्य छोटे अपराधों के मामलों जिसमें यातायात उल्लंघन के मामलों को भी शामिल कर निराकृत किये जायेंगे। विगत लोक अदालत की भांति राजस्व न्यायालय के प्रकरणों के संबंध में भी 13 जुलाई को खण्डपीठों का गठन करते हुए, खातेदारों के मध्य आपसी बंटवारे, वारिसों के मध्य बंटवारे, याददाश्त के आधार पर बंटवारे, कब्जे के आधार बंटवारे के प्रकरण, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 की कार्यवाही के मामले, भाड़ा नियंत्रण सम्बन्धी, सुखाधिकार सम्बन्धी, विक्रयपत्र, दानपत्र, वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरण के मामले तथा अन्य राजीनामा योग्य मामले रखे जाएंगे।

यदि किसी पक्षकार का मामला राजीनामा योग्य है तथा वह आयोजित होने वाली इस लोक अदालत का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो वह जल्द से जल्द स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने मामले को राजीनामा हेतु आयोजित होने वाली इस वर्ष की द्वितीय नेशनल लोक अदालत 13 जुलाई 2024 में रखने हेतु संबंधित न्यायालय से अनुरोध कर सकता है तथा मुकदमा पूर्व प्रकरण न्यायालय परिसर स्थित प्रबन्ध कार्यालय के हेल्प डेस्क में प्रस्तुत कर सकता है।

संपादकीय

जनादेश के मायने

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1969-70 सीरीज के दौरान खेले गए दिल्ली क्रिकेट टेस्ट शुरू होने के पहले का एक मशहूर वाकया है। कंगारुओं को उन दिनों विश्व की सबसे शक्तिशाली टीम समझा जाता था। मैच शुरू होने के पहले मेहमान टीम के कप्तान बिल लॉरी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनके खिलाड़ी भारतीय टीम को तीन दिन के भीतर हराकर बचे हुए समय में मछली मारने चले जाएंगे। लेकिन हुआ इसका ठीक उलटा। मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह से शिकस्त दी, जिससे लॉरी की काफी किरकिरी हुई। क्रिकेट विश्लेषकों के अनुसार ऑस्ट्रेलियाई टीम का अति आत्मविश्वास उसे ले डूबा।

अभी-अभी संपन्न हुए देश के आम चुनाव के परिणामों की घोषणा के बाद कई सियासी जानकारों का मानना है कि अत्यधिक आत्मविश्वास के कारण ही भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते बहुमत पाने में सफल नहीं हो सकी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव पूर्व गठित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने सरकार बनाने के लिए आवश्यक 272 से अधिक सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन पार्टी के ज्यादातर समर्थक इस परिणाम से निराश दिखे। ऐसा लगा मानो वे इसके लिए तैयार न थे।

आम तौर पर किसी गठबंधन के लिए बहुमत की संख्या से 20 सीटें अधिक मिलना सुकून देना वाला जनादेश होता है, लेकिन भाजपा के लिए यह परिणाम अप्रत्याशित रूप में सामने आया। इसके कुछ बड़े कारण नजर आते हैं। पहला, भाजपा ने 'अबकी बार 400 पार' का नारा देकर अपने समर्थकों की उम्मीदें हद से ज्यादा बढ़ा दी थीं। हालांकि उसे चुनावी हकीकत में उतारना असंभव नहीं, तो अव्यावहारिक जरूर था। दूसरे, इस निराशा की आग में एग्जिट पोल के नतीजों ने भी घी डालने का काम किया। लगभग सभी एग्जिट पोल ने एनडीए को लोकसभा की 350 से 400 तक सीटें जीतने का पूर्वानुमान किया था, जिसके कारण भाजपा समर्थक पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलने के प्रति आश्वस्त दिखे। तीसरे, भाजपा का पूरा चुनाव तंत्र सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी ब्रांड पर आश्रित दिखा। हालांकि प्रधानमंत्री ने अपनी ओर से मेहनत करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उनकी पार्टी के अधिकतर सांसद और उम्मीदवार 'ब्रांड मोदी' के बल पर ही अपनी चुनावी नैया पार कराने का ख्वाब देखते रहे। इस कारण कई क्षेत्रों में चुनाव के दिन पार्टी कार्यकर्ताओं की निष्क्रियता दिखी।

सरकार के सामने परीक्षा की घड़ी

प्रेमपाल शर्मा

आखिरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को यह स्वीकार करना पड़ा कि मेडिकल कालेजों में दाखिले के लिए हुई राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट-यूजी में कुछ गड़बड़ी हुई है। फिलहाल गड़बड़ी की व्यापकता का पता चलना शेष है, लेकिन नीट में अनियमितता का मामला नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के लिए बहुत ही शर्म की बात है। वर्ष 2017 में इस एजेंसी का गठन इसीलिए हुआ था कि देश भर में मेडिकल, इंजीनियरिंग, कानून तथा अन्य शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षाओं को इस तरह व्यवस्थित किया जाए कि उनमें गड़बड़ी की आशंका न रहे और लाखों-करोड़ों युवा अपनी मेधा के बूते आगे बढ़ें। हमारे देश में जिस तरह अनैतिकता फैल चुकी है, उसे देखते हुए साफ-सुथरी प्रवेश या फिर प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन एक बड़ी चुनौती बन गया है। देश के ज्यादातर राज्यों में स्कूली स्तर से लेकर विश्वविद्यालय के शोध पत्रों तक में नकल के मामले खुलेआम सामने आते हैं।

मेडिकल कालेजों में नामांकन के लिए देश के 20 लाख से अधिक युवा रात-दिन मेहनत करके तैयारी करते हैं। कई बार पढ़ाई के तनाव में वे डिप्रेशन के भी शिकार हो जाते हैं और कुछ आत्महत्या तक कर लेते हैं। इस तरह की खबरें आए दिन हमें पढ़ने को मिलती हैं। इस दौरान उनके अभिभावक भी कई समस्याओं से गुजरते हैं, विशेषकर गरीब अभिभावक। अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए वे एक यकीन के साथ उनके समर्थन में खड़े रहते हैं। ऐसे में जब पेपर लीक होने या फिर परिणाम में धांधली की कोई खबर आती है तो उन्हें कितनी गहरी निराशा और पीड़ा होती होगी, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। इस बार नीट-यूजी में कहीं केंद्र बदले गए, कहीं समय का ध्यान नहीं रखा गया और अंत में पेपर लीक होने की भी बात सामने आई। इसी के साथ ग्रेस मार्क्स देने का मामला भी सामने आया। यह किसी के लिए समझना कठिन था कि ग्रेस मार्क्स किस आधार पर दिए गए? जब एनटीए ग्रेस मार्क्स देने के अपने तर्कों का बचाव नहीं कर सका तो फिर उन्हें रद कर दिया गया।

देश में वर्षों से प्रवेश और प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। इनमें शामिल लोग पकड़े भी जाते हैं, लेकिन सवाल यह है कि उसके बाद क्या होता है? क्या उनको ऐसी सजा मिलती है, जो एक नजीर बन सके? सिर्फ परीक्षा कराने में शामिल एजेंसियों का लाइसेंस रद्द करना या फिर सरकारी कर्मचारियों को निलंबित करना ही पर्याप्त नहीं है। वे तो इस धंधे में संलिप्त होकर पहले ही करोड़ों रुपये कमा चुके होते हैं और छोटं-मोटे दंड के लिए भी मानसिक रूप से तैयार रहते होंगे। उनको गिरफ्तार करके उन्हें जेल में बंद कर उनके साथ अपराधियों की तरह पेश आना चाहिए, भले ही हमारे लिबरल और उनके पोषक-प्रोत्साहक कुछ भी कहते रहें। इस बात के पुख्ता प्रमाण हैं कि देश में कुछ गिरोह दशकों से इसी काम में लगे हुए हैं। वे कभी पुलिस, कभी शिक्षक, क्लर्क आदि की भर्ती के लिए होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली के लिए सक्रिय होते हैं, तो कभी अन्य संस्थाओं में दाखिले के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षाओं में उनकी घुसपैठ रहती है। हर परीक्षा उनके लिए भ्रष्टाचार और बेईमानी का एक मौका है। ऐसा नहीं है कि सरकारें इस समस्या से अनजान हैं और हाथ पर हाथ धरे बैठी हैं।

पिछले दिनों सरकार के स्तर पर परीक्षाओं में कदाचार को लेकर खूब चर्चा हुई। इसे रोकने और परीक्षाओं को पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के लिए संसद में एक बिल भी लाने की तैयारी चल रही है। अब इसमें देरी नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि बार-बार ऐसी खबरों से पूरे देश का मनोबल टूट जाता है। हारकर मेधावी युवा डाक्टरी से लेकर इंजीनियरिंग और अन्य विषयों की शिक्षा के लिए भी विदेश की तरफ देखने को मजबूर हो रहे हैं। हर साल देश के 10-12 लाख बच्चों का विदेश में शिक्षा के लिए पलायन हमारे लिए चेतावनी है। इससे न सिर्फ देश का बहुत सारा पैसा बाहर जा रहा है, बल्कि प्रतिभाओं से भी हम हाथ धो रहे हैं। चंद्रमा से लेकर सूर्य मिशन तक संचालित करने वाले हमारे देश के लिए बिना किसी गड़बड़ी के परीक्षाएं कराना असंभव नहीं होना चाहिए। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) हर साल करीब 12 लाख परीक्षार्थियों की परीक्षा आयोजित करता है। रेलवे ने तो एक-एक करोड़ परीक्षार्थियों की परीक्षा ली है। आखिर एनटीए इनसे सबक क्यों नहीं सीखती? एक सवाल यह भी है कि क्या देश की हर समस्या का समाधान न्याय पालिका खासकर सुप्रीम कोर्ट ही निकालेगा? जब नीट-यूजी में हुई गड़बड़ी को लेकर लोगों ने शिकायत की तो कार्यपालिका और उसकी संस्थाओं ने पहले चुप्पी क्यों साध ली? राहत के लिए लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी?

इसमें दो राय नहीं कि मोदी सरकार को अपने तीसरे कार्यकाल में सख्ती से कार्यपालिका और नौकरशाही को दुरुस्त करना होगा। क्या शीर्ष पदों पर बैठे अधिकारी संस्थाओं की शोभा बढ़ाने और वेतन एवं पेंशन आदि सुविधाओं की हकदारी के लिए ही हैं? सरकार को चाहिए कि वह इन नकली सेवकों को भी कुछ सबक सिखाए। यदि नौकरशाही ठीक से काम करे तो ऐसा कोई कारण नहीं कि हर क्षेत्र में व्यवस्थागत सुधार न हो सके, लेकिन उससे पहले राजनीतिक सत्ता को भी अपने चाल-चलन को बदलना होगा। नीट-यूजी में गड़बड़ी को मोदी सरकार को एक खतरे की घंटी के रूप मे लेने की जरूरत है।

एनडीए सरकार,चौतरफा चुनौतियां

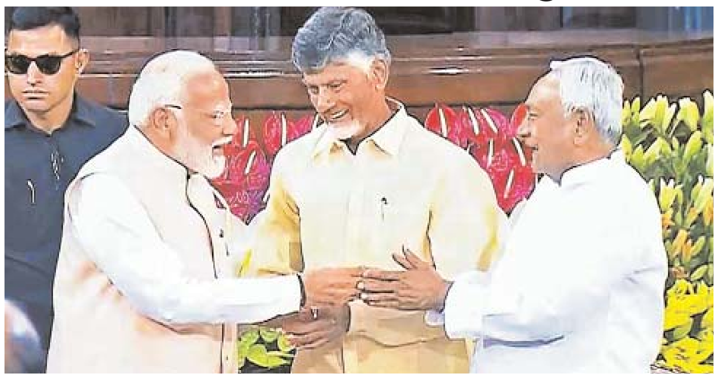

हरिमोहन मिश्र

याद कीजिए, पिछले दस वर्षों में ऐसा कब हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे, वह भी जी-7 देशों के शिखर सम्मेलन में गए हों और देश में सुर्खियां 'नीट' परीक्षा में कथित धांधली, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बेरुखी वगैरह उगल रही हों; गली-मोहल्ले, गांव-खेड़े में चर्चाएं बाहर से ज्यादा भाजपा और संघ परिवार के भीतर से उठ रही चुनौतियों की हो रही हों; हारे हुए भाजपा नेता खुलकर भितरघात के आरोप-प्रत्यारोपों में उलझे हों; विपक्ष लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद पर मोर्चे खोल चुका हो; मुंबई में ईवीएम में मोबाइल से छेड़छाड़ के कथित आरोप की एफआइआर कोई मतगणना अधिकारी करा रहा हो बेशक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तीसरी पारी की एनडीए सरकार में वित्त, रक्षा, गृह, विदेश मामले और वाणिज्य जैसे प्रमुख मंत्रालयों (सरकार की प्रभावी सत्ता का 85 प्रतिशत) को भाजपा के पाले में रखकर और पुराने मंत्रियों को ही गद्दी सौंपकर यह संदेश दिया कि सब कुछ वैसा ही चलेगा जैसा वे चाहते हैं, लेकिन तूफान के संकेत की तरह चुनौतियां नई-नई शक्ल में खुल रही हैं- सिर्फ सियासी नहीं, दूसरे मोर्चों पर भी। अशुभ योग भी दिख रहे हैं। सिर मुंड़ाते ही ओले की तरह पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में रेल दुर्घटना आ गिरी, जिसमें प्रारंभिक खबरों के मुताबिक नौ लोग जान गंवा बैठे और यह रेल व्यवस्था में सुधार के दावों की पोल एक बार फिर खुलती लग रही है।

दरअसल जनादेश 2024 ही कड़ी और अप्रत्याशित चुनौतियों की राह खोलता है। ये चुनौतियां सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्ष इंडिया दोनों के दरवाजे पर खड़ी हैं, हालांकि सत्ता पक्ष के लिए ये बेशक मुश्किलजदा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 543 सदस्यीय लोकसभा में 272 सीटों के साधारण बहुमत से पीछे रुक गई। उसे 240 सीटें ही मिलीं, जो जरूरी आधे आंकड़े से 32 कम हैं। इससे पहली बार मोदी की अगुआई वाली सरकार अपने 24 एनडीए सहयोगियों की बैसाखी पर टिकी है, जिन्हें 53 सीटें मिली हैं। लिहाजा, यह कई तरह की मजबूरियां, विरोधाभास और टकराव की संभावनाएं लिए हुए है। उन्हें संभालना आसान तो नहीं रहने वाला है।

मोदी अब तक बहुमत वाली सरकारों की ही अगुआई करते रहे हैं, चाहे 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हों या 2014 से 2024 के बीच देश के प्रधानमंत्री। अलबत्ता उन्होंने इस धारणा को फौरन झटक दिया कि उनका गठबंधन की राजनीति से कोई साबका नहीं है और कोर्स करेक्शन या कहिए झुकने से उन्होंने परहेज नहीं दिखाया है। राजनैतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव कहते हैं, ''मोदी बैकफुट पर खेलने के आदी नहीं हैं। वे आक्रामक मुद्रा ही दिखाएंगे।'' इसके संकेत लेखिका अरुंधती राय और डॉ. शेख शौकत हुसैन के खिलाफ 2010 में कश्मीर को लेकर एक बयान के मामले में आतंकरोधी यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने के दिल्ली के उप-राज्यपाल की संस्तुति में दिखे भी, हालांकि मामला यूएपीए की जमानती धारा 13 में दर्ज किया गया है। ऐसे ही सहारनपुर तथा कई जगहों पर छटिपुट झड़पों, ओडिशा के बालेश्वर में दंगे और उत्तर प्रदेश की अयोध्या से जुड़ी फैजाबाद सीट पर भाजपा की हार के लिए वहां के लोगों के खिलाफ ट्रोल आर्मी की अपमानजनक टिप्पणियों में भी झलकता है।

बस्तर अंचल को कुपोषण मुक्त बनाने मिशन मोड में कार्य करने पर जोर

सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती आबिदी ने विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा की

जगदलपुर। महिला बाल विकास विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी ने जगदलपुर कलेक्टोरेट के प्रेरणा सभाकक्ष में विभागीय गतिविधियों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन स्थिति की विस्तृत समीक्षा बैठक लेकर धरातल पर हो रही प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को मिशन मोड पर कार्य कर बस्तर अंचल को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए व्यापक सहभागिता निभाने पर जोर दिया। साथ ही कहा कि माताओं-बहनों को शासन की सभी योजनाओं से शत-प्रतिशत लाभान्वित कर बस्तर ईलाके में विकास की बयार को सोशल सेक्टर में भी बेहतर प्रदर्शन करने कहा।

सचिव श्रीमती आबिदी ने एकीकृत बाल विकास सेवाओं को धरातल में कारगर ढ़ंग से सुलभ कराने के निर्देश देते हुए कहा कि शासन की अन्य कल्याणकारी योजनाओं से भी क्षेत्र के महिलाओं को योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाया जाना है। इस दिशा में सेवाओं को परिणामदायी बनाने हेतु जनजागरूकता लाने सहित सेवाओं की गुणवत्ता एवं सेवाओं के विस्तार के लिए प्रभावी पहल किया जाए। सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि महिला बाल विकास विभाग की महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना, रेडी-टू-ईट, नोनी सुरक्षा योजना का लाभ सभी हितग्राहियों को मिले। उन्होंने गर्भवती, शिशुवती माताओं, बच्चों और किशोरी बालिकाओं का नियमित अंतराल पर स्वास्थ्य परीक्षण, टीकाकरण और वजन लेने कहा। वहीं स्कूल पूर्व प्रारंभिक शिक्षा, पूरक पोषण आहार तथा पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा को परिणाममूलक बनाने के लिए संवेदनशीलता के साथ दायित्व निर्वहन किये जाने के निर्देश दिए।

सचिव महिला एवं बाल विकास ने पोषण पुनर्वास केन्द्रों पर कुपोषित बच्चों के उपचार के लिए नियमित रूप से शत-प्रतिशत बिस्तरों के अनुरूप भर्ती करने कहा। इस हेतु प्रत्येक 15 दिवस में भर्ती करने के लिए कुपोषित बच्चों का रोस्टर तैयार कर लाभान्वित किये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनांतर्गत निर्धन जरूरतमन्द महिलाओं को लाभान्वित कर योजना के उद्देश्य की सार्थकता साबित करने कहा। वहीं मिशन वात्सल्य के अंतर्गत बाल देखरेख संस्थाओं में निवासरत बच्चों को नियमित स्कूल या ओपन स्कूल के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने एवं उन्हें कौशल विकास प्रशिक्षण देने के लिए कार्ययोजना प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिए।

बैठक में बेटी-बचाओ, बेटी-पढ़ाओ सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती, आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण की स्वीकृति, संचालित एवं प्रगतिरत भवनों इत्यादि की समीक्षा की गई।

बैठक में महिला बाल विकास विभाग की संचालक सुश्री तुलिका प्रजापति सहित महिला बाल विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों सहित बस्तर, बीजापुर, दन्तेवाड़ा एवं सुकमा जिले के जिला स्तरीय अधिकारी और बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं सुपरवाइजर्स उपस्थित थे।

देश की जरूरत के मुताबिक कृषि क्षेत्र में रहें अपडेट- नेताम

रायपुर। कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम ने कहा है कि देश में कृषि और उद्यानिकी के विकास में कृषि वैज्ञानिकों को महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कृषि वैज्ञानिकों को वर्तमान दौर में लोगों के जरूरत के मुताबिक कृषि क्षेत्र में अपडेट रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आजादी के पहले देश में भुखमरी की स्थिति थी। आवश्यकता के अनुरूप अनाज का उत्पादन नहीं हो पाता था, जिसके कारण अन्य हमें देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। हमारे देश के कृषि वैज्ञानिकों, रिसर्चर, प्रोफेसर के नीत नए तकनीकों की खोज और उत्पादन में वृद्धि के प्रयास का प्रतिफल है कि आज हमारे पास अन्न का पर्याप्त भंडार है और दूसरे देशों को निर्यात भी करते हैं।

मंत्री श्री नेताम कृषि महाविद्यालय रायपुर में आयोजित तीन दिवसीय छत्तीसगढ़-मध्यप्रदेश के कृषि विज्ञान केन्द्रों की 31वीं क्षेत्रीय कार्यशाला' के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। मंत्री श्री नेताम ने इस मौके पर कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा लगायी गयी प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा पत्रिकाओं का विमोचन किया।

कृषि मंत्री श्री नेताम ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने "एक गांव, एक फसल" का आव्हान किया है। देश को सक्षम और समृद्धशाली बनाने के प्रधान मंत्री श्री मोदी के इस सोंच के अनुरूप कृषि वैज्ञानिकों और इस क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों को नवीन तकनीक और दलहन-तिलहन व मिलेट्स फसलों का खोज कर उत्पादन में वृद्धि करने की दिशा में कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश भर में अनेक जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित हैं। कृषि विज्ञान केन्द्रों के वैज्ञानिक का रिसर्च और किसानों में विभिन्न फसलों के प्रति जागरूकता उनकी महती योगदान को दर्शाता है।

जल जीवन मिशन के कार्यों में लापरवाही, हटाए पर गए ईई

बलरामपुर। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने जल जीवन मिशन के कार्यों में संतोषजनक प्रगति नहीं पाए जाने पर बलरामपुर खंड के प्रभारी कार्यपालन अभियंता को हटा दिया है। विभागीय समीक्षा बैठक में बलरामपुर जिले में जल जीवन मिशन के कार्यों में वांछित प्रगति नहीं होने तथा लक्षित कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने में कठिनाई पाए जाने पर विभाग ने वहां के प्रभारी कार्यपालन अभियंता श्री आदित्य प्रताप को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख अभियंता द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किया गया है।

प्रमुख अभियंता द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि विगत 20 जून को हुई राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में यह परिलक्षित हुआ है कि बलरामपुर जिले में जल जीवन मिशन का कार्य संतोषजनक नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि बलरामपुर खंड के प्रभारी कार्यपालन अभियंता द्वारा अपने दायित्वों एवं कर्तव्यों के निर्वहन में उदासीनता बरतने के कारण विभागीय कार्य प्रभावित हो रहे हैं। जल जीवन मिशन के लक्षित कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने के लिए वांछित गति नहीं दिए जाने से बलरामपुर जिले में मिशन के उद्देश्यों के अनुरूप वांछित प्रगति प्राप्त करने में कठिनाई आ रही है।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के बलरामपुर खंड के प्रभारी कार्यपालन अभियंता श्री आदित्य प्रताप को आगामी आदेश तक बिलासपुर परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता कार्यालय में कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। उनके स्थान पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंडल अंबिकापुर के अधीक्षण अभियंता कार्यालय में सहायक अभियंता श्री सुशील कुमार सिन्हा को बलरामपुर खंड के कार्यपालन अभियंता का प्रभार सौंपा गया है।

परीक्षा में न हो कोई चूक, गोपनीयता का हो पूरा पालन -कलेक्टर

प्री बीएड एवं प्री डीएलएड परीक्षा हेतु केंद्राध्यक्षों की ली बैठक

कोरबा। कलेक्टर श्री अजीत वसंत ने छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल रायपुर द्वारा रविवार 30 जून को आयोजित होने वाली प्री बी-एड एवं प्री डीएलएड 2024 परीक्षा के संबंध में नोडल अधिकारी सहित केंद्राध्यक्षों की बैठक ली। उन्होंने परीक्षा हेतु संबंधित केंद्रों में आवश्यक तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि परीक्षा का कार्य विश्वसनीयता, गोपनीयता और गंभीरता से जुड़ा होता है। इस कार्य में किसी प्रकार की चूक व लापरवाही न की जाए। परीक्षा का संचालन दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए संपन्न किया जाए। उन्होंने केंद्राध्यक्षों को सावधानी एवं सतर्कता के साथ परीक्षा संपन्न कराने के निर्देश दिए।

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्री बीएड एवं प्री डीएलएड 2024 परीक्षा के संबंध में बैठक लेते हुए कलेक्टर ने सभी केंद्राध्यक्षों को उनके कर्तव्यों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में दी जाने वाली आवश्यक सुविधाएं परीक्षा के पूर्व सुनिश्चित कर ली जाएं। परीक्षा के संबंध में व्यापम द्वारा जो भी दिशा-निर्देश है उसका पालन करते हुए केंद्र में आवश्यक व्यवस्था की जाए। कलेक्टर ने परीक्षार्थियों की सुविधा हेतु बनाए गए मार्गदर्शन केंद्र के माध्यम से उनकी समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। इस दौरान नोडल अधिकारी श्री विकास चौधरी, परीक्षा समन्वयक डॉ. श्रीमती साधना खरे उपस्थित थीं।

परीक्षा दो पालियों में आयोजित होगी। जिले में 34 परीक्षा केंद्रों पर 11,981 एवं द्वितीय पाली 43 परीक्षा केंद्रों में 14,884 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे।

वरिष्ठ अधिकारियों ने दी शासकीय नियमों, कानूनों और कार्यों की विस्तृत जानकारी

सारंगढ़-बिलाईगढ़। कलेक्टर श्री धर्मेश कुमार साहू के निर्देश पर जिले में आयोजित शासकीय विभागों के नियम, कानून और कार्यों के दो दिवसीय कार्यशाला का समापन हुआ। समापन दिवस में मार्गदर्शन देते हेतु वरिष्ठ सेवानिवृत विशेष सचिव श्री पी. निहलानी ने भू-अर्जन विषय पर विस्तृत जानकारी दिए। कार्यशाला की शुरुआत में राजस्व विभाग के अधिकारियों ने कार्य में आ रही समस्याओं के बारे में पूछा। श्री निहलानी ने समाधान हेतु आवश्यक सुझाव दिए। उन्होंने भू-अर्जन अधिनियम में सुधार एवं नये अधिनियम की आवश्यकता के संबंध में जानकारी दी। साथ ही पुर्नवास एवं पुर्नव्यस्थापन के संबंध में अपडेट किए गये नियमों की जानकारी दी। इसके साथ ही इस नये अधिनियम में जुड़े नये जटिल शब्दों की व्याख्या की एवं भू-अर्जन के पूर्व सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन किए जाने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी।

कार्यक्रम में श्री अशोक तिवारी (सेवानिवृत) ने वासिल बाकी नवीस के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए माँग की पंजियों के संधारण, बैंक में जमा की जाने वाली राशि एवं वसूली राशि, भू-राजस्व एवं विविध राजस्व, भू राजस्व संहिता की धारा-57 एवं धारा-59, बी-1, किस्तबंदी, आरबीसी की कंडिकाएं, जुर्माना एवं शास्तियाँ, विभागीय जाँच एवं कार्यवाही, नजूल संबंधी प्रकरण, स्थापना शाखा के अंतर्गत पदस्थापना पदोन्नति प्रक्रिया, डीपीसी बैठक, अधिकारियों कर्मचारियों के सेवा पुस्तिकाओं का संधारण, राजस्व न्यायालय की प्रक्रिया तथा राजस्व मुहर्रिर शाखा के कामकाज इन सभी विषयों पर अपना आख्यान दिया।

इसके पश्चात अतिरिक्त तहसीलदार बिलासपुर शशिभूषण सोनी ने ई-कोर्ट एवं भुइयां पोर्टल के संबंध में जानकारी दी?। नायब तहसीलदार उज्जवल पाण्डेय ने नजूल संबंधी प्रकरणों के संबंध में जानकारी दी। इसके पश्चात् जिला आबकारी अधिकारी रायगढ़ रामकृष्ण मिश्रा ने आबकारी प्रकरणों के संबंध में जानकारी दी। इसी क्रम में खनिज शाखा से सहा. खनिज अधिकारी कोरबा उत्तम खुंटे एवं खाद्य विभाग बिलासपुर से राजीव लोचन तिवारी ने संबंधित जानकारी दिए। इसके अलावा कार्यालय बिलासपुर के कर्मचारियों वित्त एवं लेखा शाखा संबंधी जानकारी दिए। इस अवसर पर एसडीएम अनिकेत साहू एवं राजस्व विभाग के समस्त अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

पाली के किसानों को किया गया बीज वितरण

कोरबा। कृषि विभाग पाली जिला कोरबा द्वारा ग्राम पुलालीकला में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना अंतर्गत श्रीविधि धान का प्रदर्शन श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम विधायक, पाली-तानाखार के मुख्य अतिथि और श्री विजय बहादुर जगत जिला पंचायत सदस्य, श्री नारायण सिंह राज सभापति कृषि स्थाई समिति पाली की उपथिति में बीज वितरण और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में विधायक द्वारा किसानों को सम्बोधित करते हुऐ उपस्थित कृषको को उन्नत तकनीक अपनाकर खेती करने की सलाह दी गई। कार्यक्रम में उपस्थित जिला पंचायत सदस्य द्वारा किसानों को प्रमाणित बीज और संतुलित खाद का उपयोग करने की सलाह दी गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम में श्री कुलदीप सिंह मरकाम विधायक प्रतिनिधि, श्री उमाशंकर कश्यप विधायक प्रतिनिधि, श्रीमती जामबाई श्याम विधायक प्रतिनिधि ,श्री जी पी डिकसेना वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी पाली, श्री ए के मरकाम एवम अजय सिंह ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी तथा ग्राम पुलालीकला,नवापारा और नानपुलाली के कृषकगण कार्यक्रम में उपस्थित थे।

धनरास में जिला पंचायत अध्यक्ष ने किया बीज का वितरण -

ग्राम पंचायत भवन धनरास कटघोरा में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शिवकला कंवर, जनपद उपाध्यक्ष श्री गोविंद सिंह कंवर ,कृषि स्थायी समिति के सभापति श्री बैसाखू राम यादव और सरपंच श्रीमती मनटोरी बाई कंवर की गरिमामयी उपस्थिति में आत्मा एवं आरकेवीवाई योजनांतर्गत कोदो बीज एवं एसएमएसपी योजनांतर्गत अरहर बीज का वितरण किया गया।

पिछले सत्र में स्कूली विद्यार्थियों के 60 हजार से ज्यादा जाति प्रमाण पत्र बने

कलेक्टर मलिक की पहल पर जाति प्रमाण पत्र बनाने विशेष अभियान चलाया गया

महासमुंद। अध्ययन के दौरान ही विद्यार्थियों के हाथों में जाति प्रमाण पत्रछत्तीसगढ़ शासन के मंशानुरूप लोक सेवा प्रदाय प्रणाली को प्रभावी एवं सरल बनाने के लिए सुशासन की दिशा में अभिनव प्रयास किए जा रहे है। जाति प्रमाण पत्र प्रदाय अभियान के तहत स्कूल के छात्र छात्राओं को जाति प्रमाण पत्र प्रदान करने जिले में सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है। पिछले शिक्षा सत्र 2023-24 में कक्षा पहली से लेकर कक्षा 12वीं तक पढ़ने वाले बच्चों के जाति प्रमाण पत्र बनाने के मामले में जिले ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। कलेक्टर श्री प्रभात मलिक ने स्कूली बच्चों के जाति प्रमाण पत्र बनाने हेतु विशेष रूचि लेते हुए सभी स्कूलों में विशेष अभियान चलाया गया। फलस्वरूप पिछले एक सत्र में ही 60 हजार 148 बच्चों के जाति प्रमाण पत्र बनाया गया जो सम्भवत: प्रदेश में सर्वाधिक है। कलेक्टर श्री मलिक ने कहा कि हम सभी को शासकीय कामकाज और अन्य कारणों से जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता हमेशा होती है, जिसके लिए लोग भटकते रहते हैं। इसलिए स्कूलों को इकाई मानकर जाति प्रमाण पत्र बनाने की पहल किया गया। जिसके कारण बड़ी संख्या में विद्यार्थियों की जाति प्रमाण पत्र बने। अध्ययन के दौरान ही बच्चों की जाति प्रमाण पत्र बनने से उन्हें और पालकों को जाति प्रमाण पत्र बनाने भटकना नहीं पड़ेगा।

विकास कार्यों की राशि का गबन करने वाला सरपंच गिरफ्तार

जगदलपुर। न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बस्तर द्वारा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 92 की उपधारा (2) के अधीन ग्राम पंचायत भानपुरी की सरपंच श्रीमती मुंगई बघेल को गिरफ्तार कर केंद्रीय जेल भेज दिया गया। सरपंच श्रीमती मुंगई बघेल के द्वारा ग्राम पंचायत, भानपुरी की वर्ष 2017-18, 2020-21, 2021-22, 2022-23 की विभिन्न 54 निर्माण कार्य की राशि 55 लाख 42 हजार 875 रूपये को प्राप्त कर निर्माण कार्य नहीं कराया गया है। एसडीएम कार्यालय द्वारा सरपंच को पंचायत के निर्माण कार्य की राशि को अपनी अभिरक्षा में रखने के लिए, राशि पंचायत को तत्काल परिदत्त या संदत्त करने के लिए नोटिस जारी किया गया था, किन्तु निर्देशित धन राशि परिदत्त करने में असफल रहने के कारण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बस्तर द्वारा श्रीमती मुंगई बघेल को पुलिस अभिरक्षा में रखते हुए अधिक से अधिक 20 दिन (26जून से 16 जुलाई 2024 तक) की कालावधि के लिए या अभिलेख प्रदत्त किये जाने तक या उक्त धन संदत्त किये जाने तक सिविल जेल में परिरुद्ध रखा गया है।

मुख्य मार्गों में गड्ढे ही गड्ढे, हो रहे हादसे

केशकाल। बस्तर की एकमात्र लाइफलाइन कहलाने वाले राष्टीय राजमार्ग 30 केशकाल के सडक की स्थिति बारिश से पहले ही बद से बदतर होती जा रही है। हालांकि विभागीय अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक 5-7 दिनों में गड्ढों में डस्ट डाल कर गड्ढे भरे जरूर जाते हैं, लेकिन महज एक घण्टे की मूसलाधार बारिश के बाद वो डस्ट बह जाता है, सडक़ पर रह जाते हैं तो बड़े बड़े गड्ढे। यह गड्ढे इतने बड़े-बड़े हो गए हैं कि बारिश होने पर इनमें पानी भर जाता है, जिससे दुपहिया व चारपहिया वाहन चालकों को गड्ढे की गहराई का अंदाजा नहीं मिल पाता। ऐसे में आए दिन छोटी छोटी सडक़ दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं।

ज्ञात हो कि राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के द्वारा केशकाल नगर और घाटी के मरम्मत के लिए प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है। जानकारों की माने तो पिछले 5 वर्षों में जितनी राशि सडक़ मरम्मत के नाम पर खर्च हुई है, इतनी राशि में नवीन सडक़ का निर्माण भी हो जाता।

राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के द्वारा करोड़ों रुपए खर्च करने बावजूद यह सडक़ मरम्मत ठीक से साल भर भी नहीं टिकती। हर साल बारिश आने से पहले ही केशकाल नगर और केशकाल घाटी के सडक़ की हालत जर्जर हो जाती है। जिसके कारण राहगीरों और आम जनता को धूल गड्ढे और कीचड़ युक्त सडक़ से होकर गुजरना पड़ता है।

45 करोड़ से जल्द सडक़ चौड़ीकरण- विधायक

इस संबंध में केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम ने बताया कि केशकाल शहर की सडक़ के लिए 45 करोड़ रुपए की लागत से एक कार्ययोजना तैयार गई है, जिसमें 45 करोड़ रुपए की लागत से नगर में सडक़ का चौड़ीकरण, डिवाइडर, सडक़ के दोनों ओर नाली निर्माण, पानी के निकासी की उचित व्यवस्था की जाएगी। हमारा प्रयास यह भी है कि केशकाल घाट व नगर की सडक़ के देखरेख की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग को दी जाएगी।

फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी लेने बलौदाबाजार कलेक्टर पहुंचे गांव

- **बिहान से जुड़कर कार्य करने वाले महिला स्व सहायता समूह के कामकाज की प्रशंसा,बताया जिले के लिए रोल मॉडल**
- **नवप्रवेशी स्कूली बच्चों से की मुलाकात, पहाड़ा पूछकर बच्चों का किया उत्साहवर्धन**

बलौदाबाजार। बलौदाबाजार- भाटापारा जिले में फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी लेने कलेक्टर दीपक सोनी ने गांवों का दौरा किया है। इस दौरान उन्होनें सिमगा विकासखण्ड के अंतर्गत ग्राम पंचायत ढेकुना के आश्रित ग्राम विश्रामपुर तथा ग्राम अडबंधा,दामाखेड़ा एवं सिमगा नगर में संचालित सहकारी सोसायटी,राशन दुकान,स्कूल भवन,पंचायत भवन का निरीक्षण,सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र,प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों से मुलाकात, जल जीवन मिशन,स्वच्छ भारत मिशन सहित अन्य विभिन्न निर्माण कार्यों का जायजा लिया।

ग्राम पंचायत ढेकुना अंतर्गत ग्राम विश्रामपुर स्थित सहकारी सोसायटी में उपस्थित किसानों और आम ग्रामीणों से मुलाकत कर खाद बीज की उपलब्धता,समय ऋण मिलने के बारे में जानकारी हासिल किए,जिस पर ग्रामीणों ने सरना बीज की कमी के बारे में शिकायत दर्ज कराया। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए श्री सोनी ने किसानों की समस्या का तत्काल निराकरण करते हुए कसडोल से बीज मंगाकर उपलब्ध कराने के निर्देश संबधित अधिकारियों को दिए है।

इसी तरह ग्राम पंचायत दामाखेड़ा में आजीविका मिशन के तहत बिहान समूह से जुड़ी महिला स्व सहायता समूह के द्वारा संचालित गतिविधियों का अवलोकन करते हुए स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित गतिविधियों से जुड़कर जीवन मे आए सकारात्मक बदलाव के सम्बंध में जानकारी हासिल की। महिलाओं ने श्री सोनी को बताया कि बिहान से जुड़कर उनकी आर्थिक स्थित में काफी सुधार आया है।

दामाखेड़ा में अन्नपूर्णा स्व सहायता समूह समिति द्वारा अगरबत्ती निर्माण,अन्य समूह द्वारा केक निर्माण एवं ग्राम अडबंधा में समूह द्वारा मछली पालन, बकरी पालन किया जा रहा है। श्री सोनी ने स्व सहायता समूह के कामकाज की प्रशंसा करते हुए पूरे जिले के लिए रोल मॉडल बताया। इस मौके पर अडबंधा में महिला स्व सहायता के समूह द्वारा बकरी शेड की मांग की गई। जिस पर कलेक्टर ने बकरी शेड स्वीकृत करने के निर्देश जिला पंचायत सीईओ को दिए है। साथ ही उन्होंने मनरेगा के तहत हुए कार्यो पर सतुष्टि जताते हुए प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि उक्त तालाब में बहुत अच्छे तरीके से मछली पालन सहित अन्य रोजगार मुलक कार्य भी किए जा सकतें है। श्री सोनी ने इसके लिए उपस्थित महिला स्व सहायता समूह के सदस्यो से चर्चा कर जायजा लिया।

कलेक्टर ने ग्राम अडबंधा के प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से लाभान्वित हितग्राहियों के घर पहुंचकर निर्मित मकान का अवलोकन किया। इस दौरान मकान मालिक एवं उनके परिवार के सदस्यों ने पक्का मकान बनने से जीवन में हुए बदलाव के बारे में अपने विचार साझा किए। इसके साथ ही ग्राम में जल जीवन मिशन के तहत चल रहे कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी प्रकट किया। इसके साथ ही पाइप बिछाने के लिए सीसी रोड के बीचो-बीच गड्ढा करने पर भी नाराजगी व्यक्त करते हुए सुधार के महत्वपूर्ण निर्देश अधिकारियों को दिए है।

कलेक्टर दीपक सोनी ने ग्राम अडबंधा के ही प्राथमिक शाला में पहुंचकर पहली कक्षा के नवप्रवेशी स्कूली बच्चों से मुलाकात की। कक्षा 5 वी के बच्चों को श्री सोनी ने पहाड़ा, जोड़ घटाना पूछकर एवं सवाल जवाब कर उनका उत्साहवर्धन किया। पहाड़ा पूछने पर बच्चों ने कलेक्टर को पूरा पहाड़ा पढ़कर सुनाया जिस पर कलेक्टर ने बच्चों को टॉफी भी भेंट की। साथ ही कलेक्टर ने बड़े होकर क्या बनने का प्रश्न किया। जिस पर बच्चों ने डॉक्टर,इंजीनियर और पुलिस बनने की बात की।

कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान उन्होंने शिक्षकों की उपस्थिति पंजी एवं मध्याह्न भोजन सहित शिक्षा की गुणवत्ता को भी परखा। इस दौरान ग्रामीणों ने स्कूल के लिए अतिरिक्त भवन को मांग की जिस पर कलेक्टर ने शीघ्र ही कार्रवाई कर निराकरण का आश्वासन दिए है।

समाधि स्थल का दर्शन कर लिया आशीर्वाद

पहली बार दामाखेड़ा पहुंचे नवपदस्थ कलेक्टर दीपक सोनी ने समाधि स्थल मंदिर पहुंचकर दर्शन लाभ लिए। इस दौरान श्री सदगुरु कबीर धर्मदास साहब वंशावली प्रतिनिधि सभा के सदस्यो ने श्री सोनी को संत कबीर दास जी के गुरुवंश परंपरा, इतिहास एवं स्थान के महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की।जिस पर कलेक्टर श्री सोनी ने पुरानी बाते साझा करते हुए बताया की मुझे यूपीएससी के इंटरव्यू में कबीर के बारे में पूछा गया था।उस समय ही मैं दामाखेड़ा के बारे में पढ़ा था आज मेरा सौभाग्य है की मुझे दामाखेड़ा आने का मौका मिला। साथ ही इस दौरान श्री सदगुरु कबीर धर्मदास साहब वंशावली प्रतिनिधि सभा के सदस्यो ने पहली बार कलेक्टर के दामाखेड़ा आने पर उन्हें श्री फल,साल एवं किताब भेंटकर सम्मान किया।

कलेक्टर ने शासन से प्राप्त लक्ष्य की पूर्ति हेतु जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी को सौंपी जिम्मेदारी

कोरिया। अंत्योदय स्वरोजगार अनुसूचित जाति एवं आदिवासी स्वरोजगार अनुसूचित जनजाति योजनान्तर्गत वर्ष 2024-25 की भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निर्धारण किया गया है। जिले को अनुसूचित जाति अंत्योदय स्वरोजगार योजना में 67 इकाई एवं अनुसूचित जनजाति आदिवासी स्वरोजगार योजना में 32 इकाई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित कोरिया श्री विनय कुमार लंगेह ने शासन से प्राप्त लक्ष्य की पूर्ति हेतु जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी को बैंकवार एवं शाखावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निर्धारण कर पात्रता रखने वाले अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के आवेदकों से ऋण प्रकरण तैयार कर संबंधित बैंक शाखाओं को स्वीकृति हेतु पत्र प्रकरण मय अनुशंसा सहित भेजने के निर्देश दिए है। उन्होंने जनपंद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी को आबंटित लक्ष्य की पूर्ति दिसम्बर 2024 तक स्वीकृत एवं वितरण की कार्यवाही पूर्ण करने को कहा है।

ऋण हेतु आवेदक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का हो, जिले का मूल निवासी, वार्षिक आय की सीमा 1 लाख 50 हजार से ऊपर न हो, आवेदक की उम्र 18 से 50 के बीच हो, आवेदक को राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आदि संलग्न करना होगा शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, शासन की किसी भी योजनान्तर्गत ऋण व अनुदान का लाभ न लिया हो प्रमाणित शपथ पत्र, व्यवसाय संबंधित अनुभव की जानकारी देनी होगी, योजनान्तर्गत आवेदक को अनुदान राशि 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रूपये दस हज़ार जो भी कम हो दिया जाएगा।

पीडब्लूडी ने जारी किए नए दिशा-निर्देश

निविदा के बाद अब तुरंत काम होगा शुरू

सड़क और सेतु निर्माण के लिए निविदा के पहले कार्यपालन अभियंता को प्रमाणित करना होगा कि 90 प्रतिशत बाधारहित भूमि उपलब्ध

रायपुर। लोक निर्माण विभाग के कार्यों में तेजी लाने और उन्हें समय पर पूर्ण करने राज्य शासन द्वारा निविदा को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। अब सड़क और सेतु निर्माण के लिए निविदा के पहले संबंधित कार्यपालन अभियंता को प्रमाणित करना होगा कि कार्य के लिए 90 प्रतिशत बाधारहित भूमि उपलब्ध है। भवन निर्माण के लिए पूरी जमीन व्यवधानरहित होने पर ही निविदा आमंत्रित की जा सकेगी। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव द्वारा विभागीय कार्यों में तेजी और कसावट लाने के निर्देश के बाद राज्य शासन ने प्रमुख अभियंता सहित सभी मुख्य अभियंताओं, अधीक्षण अभियंताओं और कार्यपालन अभियंताओं को इस संबंध में परिपत्र जारी किया गया है। विभाग ने नए दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। इनका समुचित पालन नहीं करने पर संबंधित अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

लोक निर्माण विभाग द्वारा मंत्रालय से प्रमुख अभियंता से लेकर सभी कार्यपालन अभियंताओं को जारी परिपत्र में निर्देशित किया गया है कि निविदा आमंत्रण के पूर्व कार्यपालन अभियंता को यह प्रमाणित करना होगा कि सड़क निर्माण के लिए सड़क की प्रस्तावित कुल लंबाई की 90 प्रतिशत लंबाई व्यवधानरहित है। साथ ही 90 प्रतिशत लंबाई में सभी प्रकार की बाधाएं जैसे भूअर्जन, वन भूमि व्यपवर्तन एवं यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया गया है तथा शेष 10 प्रतिशत भूमि बाधारहित करने की कार्यवाही 180 दिनों में पूर्ण कर ली जाएगी। विभाग ने भवन निर्माण के लिए 100 प्रतिशत व्यवधानरहित भूमि उपलब्ध होने के बाद ही निविदा आमंत्रण की कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।

परिपत्र में कहा गया है कि सेतु कार्यों के पहुंच मार्ग के लिए 90 प्रतिशत लंबाई बाधारहित होने पर ही निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जाए। निविदा आमंत्रण के पूर्व कार्यपालन अभियंता को यह प्रमाणित करना होगा कि पुल निर्माण हेतु पुल के पहुंच मार्ग के लिए प्रस्तावित कुल लंबाई की 90 प्रतिशत लंबाई व्यवधानरहित है। साथ ही 90 प्रतिशत लंबाई में सभी प्रकार की बाधाएं जैसे भूअर्जन, वन भूमि व्यपवर्तन एवं यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा शेष 10 प्रतिशत भूमि बाधारहित करने की कार्यवाही 180 दिनों में में पूर्ण कर ली जाएगी। विशेष प्रकरणों में शासन द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

Public Works Department
PWD
Government of Chhattisgarh
लोक निर्माण विभाग

सिर्फ डिग्री की गिनती के फेर में न रहे, काबिलियत के लिए पढ़ें- वित्त मंत्री चौधरी

- वित्त मंत्री की छात्रों को सलाह- सही समय पर सही प्लानिंग सफल करियर का आधार
- करियर संबंधी मार्गदर्शन देने ओ.पी.चौधरी बच्चों के बीच पहुंचे,सुनाए अपने जीवन अनुभव, दिए कई महत्वपूर्ण टिप्स

रायगढ़। सिर्फ डिग्री पा लेना और उसकी संख्या बढ़ाना आपको कामयाबी के मुकाम तक नहीं लेकर जायेगा, स्किलफुल बनेंगे तो कामयाबी जरूर मिलेगी। इसलिए गिनती के फेर में न पड़ें और काबिलियत के लिए पढ़ें, वित्त मंत्री श्री ओ.पी.चौधरी ने करियर काउंसलिंग के दौरान बच्चों को यह सलाह दी। वे आज स्कूल और कॉलेज के बच्चों के बीच उन्हें करियर संबंधी मार्गदर्शन देने जिला प्रशासन द्वारा आयोजित 'उत्कर्ष-भविष्य का निर्माण' कार्यक्रम में पहुंचे थे। उन्हें सुनने बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों के साथ शिक्षक और पालक भी पहुंचे थे।

वित्त मंत्री श्री ओ.पी.चौधरी ने एक घंटे के अपने संबोधन में छात्रों को अपनी अब तक जीवन अनुभवों को साझा किया। उन्होंने बताया कि एक छोटे से गांव से निकल कर देश के प्रतिष्ठित आईएएस सेवा में चयन, प्रशासनिक करियर से लेकर राजनीतिक जीवन में प्रवेश और अब प्रदेश के वित्त मंत्री के रूप में कार्य करने का सफर कैसा रहा, क्या चुनौतियां रहीं, उनसे कैसे निपटे और भविष्य के लिए और बड़े लक्ष्य कैसे तय किए और उन्हें कैसे पूरा किया।

वित्त मंत्री श्री ओ.पी.चौधरी ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि 11 साल की उम्र में अपनी मां के साथ जब रायगढ़ के कलेक्टर ऑफिस पहली बार आया था तभी से मन में ठान लिया था कि आगे चल कर आईएएस बनना है। इस सपने को मैने जिया, लगातार मेहनत की और 23 साल की एज में सबसे कम उम्र में से एक आईएएस बनने की उपलब्धि हासिल हुई। उन्होंने कहा कि बायंग गांव से निकल कर जब मैं आईएएस बन सकता हूं जिसके पिता का देहांत 8 वर्ष की उम्र में हो गया था और मां सिर्फ चौथी तक पढ़ी है तो आप में से हर कोई अपना सपना पूरा कर सकता है। बशर्ते आपको परिस्थितियों से हारना या घबराना नहीं है बल्कि उनका सामना करना है। संकल्प यदि मजबूत होगा तो विकल्पों की कमी नहीं होगी। हमारे सामने अनेकों उदाहरण हैं जो बताते हैं कि विषम परिस्थिति में भी अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने वाले सफलता की नई इबारत लिखते हैं। उन्होंने विराट कोहली के पिता के निधन के दिन अपनी टीम के लिए खेली गई बहुमूल्य पारी, आनंद कुमार के संघर्षों के बारे बताते हुए कहा कि इन सभी सफल लोगों ने कठिन परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी होने नही दिया बल्कि उससे लड़े और जीते। उन्होंने बताया कि आईएएस की नौकरी छोड़ने के बाद कृषि कार्य और शेयर मार्केट में ट्रेडिंग का काम सीखा। खेती-किसानी के वैज्ञानिक तरीकों का ज्ञान लिया, रिसर्च किया, एग्रोनॉमिक्स विशेषज्ञों से सीखने की कोशिश की जिसका पूरा लाभ आज उन्नत कृषि में ले रहा हूं। यह सब बताने के पीछे का अर्थ यह है कि आप समझ लें कि जो करना चाहते हैं उसके बारे में पूरा ज्ञान लीजिए, एक्सपर्ट से सीखिए उसे अप्लाई कीजिए फिर कमाल देखिए। अंत में उन्होंने कहा कि सफलता और असफलता प्रयासों लेना दो ही परिणाम हो सकते हैं। असफल होने पर निराश नहीं होना है। कोई अनुचित कदम नहीं उठाना चाहिए। हमेशा याद रखें कि जिंदगी किसी एक एग्जाम, किसी एक प्रयास से कहीं ज्यादा कीमती है। इसलिए हमेशा सकारात्मक अप्रोच रखें। उन्होंने कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल और सीईओ जिला पंचायत के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित करियर गाइडेंस सेमिनार की सराहना की और कहा कि इस कार्यक्रम का नियमित आयोजन किया जाए जिससे छात्रों से संवाद बना रहे।

कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल ने भी बच्चों को संबोधित किया। उन्होंने बच्चों से अपने समय का सदुपयोग करने और देश के भविष्य में अपना योगदान देने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि यह समय महत्वपूर्ण है इसमें की गई मेहनत के जो परिणाम मिलते हैं उसका असर पूरे जीवन की दशा दिशा तय करते हैं।

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग पटेल, सीईओ जिला पंचायत श्री जितेन्द्र यादव, श्री गुरूपाल भल्ला, श्री मुकेश जैन, श्रीकांत सोमावार, श्री सुभाष पाण्डेय, श्री विवेक रंजन सिन्हा, नेता प्रतिपक्ष नगर निगम श्रीमती पूनम सोलंकी, शोभा शर्मा सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

मरीज के इलाज में लापरवाही का आरोप, प्रभारी सिविल सर्जन निलंबित

बैकुण्ठपुर। कोरिया जिला के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार डॉ. राजेन्द्र बंसारिया, अस्थिरोग विशेषज्ञ एवं प्रभारी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय बैकुण्ठपुर द्वारा मरीज का ऑपरेशन करने हेतु राशि की मांग की गई थी तथा मरीज के परिजनों द्वारा राशि नहीं दिए जाने के कारण मरीज का इलाज नहीं किया गया।

डॉ. बंसारिया के इस कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 का उल्लंघन माना गया है। अतः राज्य शासन ने डॉ. राजेन्द्र बंसारिया को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

डॉ. राजेन्द्र बंसारिया को मुख्यालय कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, सरगुजा संभाग, अंबिकापुर निर्धारित किया गया है। सक्षम अधिकारी की अनुमति एवं पूर्व स्वीकृति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। निलंबन अवधि में डॉ. राजेन्द्र बंसारिया मूलभूत नियम 53 के तहत जीवन निर्वाह भत्ते के नियमानुसार पात्र होंगे।

लिटिया जनसमस्या निवारण शिविर में 282 आवेदन निराकृत

- अधिकारियों ने दी विभागीय योजनाओं की जानकारी
- शिविर का उद्देश्य शासन-प्रशासन को जनता के करीब लाना है- कलेक्टर सुश्री चौधरी
- हितग्राही मूलक योजनाओं से लोग हुए लाभान्वित

दुर्ग। जिले के धमधा विकासखंड के ग्राम लिटिया में जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर आयोजित की गई। कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के मार्गदर्शन में ग्रामीणों की समस्याओं को सुनने, समझने और त्वरित निराकरण के लिए आयोजित इस शिविर में समस्त विभाग के अधिकारी सम्मिलित हुए। शिविर में विभिन्न विभागों को कुल प्राप्त 357 में से 282 आवेदनों का मौके पर निराकरण किया गया। शेष लम्बित 75 आवेदनों के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है।

शिविर के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने अपने सम्बोधन में कहा कि शिविर के माध्यम से शासन-प्रशासन को जनता के करीब लाना है। उन्होंने कहा कि शिविर में अधिकारियों ने विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की विस्तारपूर्वक जानकारी दी है। साथ ही समाधान योग्य आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया। कलेक्टर ने लंबित आवेदनों के संबंध में एसडीएम और जनपद सीईओ को संबंधित विभागों से त्वरित निराकरण कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को लिटिया में आईटीआई के लिए जमीन उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया है। साथ ही यहां पर बैंक खोलने के लिए भी प्रयास किया जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि जिले के किसानों की समस्याओं पर भी प्रशासन विशेष ध्यान दे रही है। कृषि विभाग के अधिकारी जिले में डीएपी खाद के विकल्प खाद का उठाव हेतु किसानों को प्रोत्साहित करें। इससे पूर्व कलेक्टर सुश्री चौधरी ने विभिन्न विभागीय स्टालों का निरीक्षण कर अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों का उचित ढंग से निराकरण करने के निर्देश दिये। कलेक्टर सुश्री चौधरी स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ महिला एवं बाल विकास विभाग के गोद भराई एवं अन्नप्राशन रस्म अदायगीय में भी सम्मिलित हुई।

शिविर में समाज कल्याण, पशुपालन, महिला एवं बाल विकास, अंत्याव्यसायी, कृषि, पंचायत, उद्यानकी, शिक्षा, आदिम जाति कल्याण, स्वास्थ्य, मतस्य, क्रेडा, विद्युत, राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गई। समीक्षा के दौरान विभागों के प्राप्त आवेदनों के निराकरण के संबंध में अधिकारियों द्वारा आवेदकों को अवगत कराया गया।

शिविर में कृषि विभाग द्वारा 5 किसानों क्रमशः मनोज साहू एवं श्री भीखम सिंह ग्राम जोगीगुफा, श्री बीरबल वर्मा एवं तारकेश्वर ग्राम लिटिया, श्री दया राम साहू ग्राम पथरिया को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत स्वीकृत बीमा राशि प्रमाण पत्र वितरित की गई। विभाग द्वारा एस.एम.एस.पी. योजना के तहत ग्राम लिटिया के 4 किसान क्रमशः श्री नंदनी दुबे एवं अनुज बंजारे को अरहर मिनीकिट और श्री फिरंता व रामेश्वर को सोयाबीन मिनीकिट प्रदान की गई।

नया कानून पुलिस, विवेचक, प्रार्थी, गवाह, पीड़ित सबके लिए एक अच्छा परिवर्तन

- कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने जनप्रतिनिधियों एवं मीडिया के प्रतिनिधियों को नये कानूनों के संबंध में दी जानकारी
- नये कानून अंतर्गत निर्धारित समय में होगा प्रकरणों का समाधान - कलेक्टर
- कानूनों में एकरूपता लाने, पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नये कानून में किया गया प्रावधान - पुलिस अधीक्षक

राजनांदगांव। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल एवं पुलिस अधीक्षक श्री मोहित गर्ग द्वारा जिला पंचायत सभाकक्ष में जनप्रतिनिधियों एवं मीडिया प्रतिनिधियों को नये अपराधिक कानूनों के संबंध में जागरूकता हेतु जानकारी दी गई। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने कहा कि एक जुलाई से भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 प्रभावी होंगे। मीडिया के माध्यम से लोगों तक नये कानूनों के संबंध में जानकारी पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि मुख्यतः पुराने कानून ब्रिटिश काल से चले आ रहे थे। जिसे प्रासंगिक बनाने के लिए एवं निर्धारित समय-सीमा में प्रकरणों का समाधान करने के लिए परिवर्तन किया गया है। इस बदलाव से अपराधियों के खिलाफ एफआईआर करने में दिक्कत नहीं होगी तथा गंभीर अपराधियों को प्रक्रिया का पालन करते हुए कड़ी कार्रवाई की जा सकेगी। प्रकरणों के निराकरण के लिए समय निर्धारित किया गया है। पीड़ित पक्ष को ध्यान में रखा गया है। शीघ्र निराकरण होने से दोनों पक्षों के लिए राहत है। पीड़ित पक्षकार को ई-साक्ष्य, जीरो-एफआईआर, ई-एफआईआर से राहत मिलेगी। बहुत अच्छी मंशा के साथ नया कानून बना है। सभी नागरिकों को इसका फायदा मिलेगा। दोषी अपराधियों को सजा जल्दी मिलेगी। जिससे समाज में एक अच्छा प्रभाव एवं परिवर्तन दिखाई देगा। पीड़ित पक्ष को न्याय जल्दी मिलेगा। यह कानून सभी नागरिकों तक पहुंच सकें। इसके लिए लगातार जानकारी दी जा रही है।

पुलिस अधीक्षक श्री मोहित गर्ग ने बताया कि 1 जुलाई 2024 से भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) के स्थान पर तीन मुख्य कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएंगे। 150 वर्ष पूर्व कानून में बदलाव किया गया है तथा अलग-अलग धाराओं में सजा के लिए परिवर्तन किया गया है। कानूनों में एकरूपता लाने के लिए नया कानून लाया गया है। उन्होंने बताया कि 7 वर्ष से ज्यादा सजा की अवधि के अपराधों में न्याय दल गठित किया जाएगा तथा साक्ष्य एकत्रित करने के बाद विश्लेषण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रकरणों के निराकरण के लिए नये कानूनों में समय का निर्धारण किया गया है। पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए है। विशेषकर अपराधिक मामलों में तलाशी एवं जप्ती के दौरान फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से की जाएगी। इन कानूनों के संबंध में नागरिकों को जानकारी होना चाहिए। नये कानून में आरोपियों के लिए नये प्रावधान किए गए हैं। सभी के लिए आवश्यक है कि स्वयं भी इन कानूनों को समझें तथा दूसरों को भी जागरूक करें। पीड़ित पक्ष को न्याय समय पर मिले। पुलिस समय पर विवेचना करें, इसके लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। लोगों के लिए एक अच्छा कानून बनाया गया है, ताकि उन्हें सुविधा मिल सकें। पुलिस, विवेचक, प्रार्थी, गवाह, पीड़ित सबके लिए एक अच्छा परिवर्तन है। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई 2024 से कानून लागू होने के बाद कोई भी अपराध होने पर नये कानून के अंतर्गत घटना या अपराध पंजीबद्ध होगा। इसके अंतर्गत अपराधों के लिए न्याय व्यवस्था अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि निर्धारित समय में उनका निराकरण हो सके। इसी तरह पुलिस एवं न्यायालय के लिए तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट समय पर देना होगा। इसमें पीड़ित पक्ष, आरोपी पक्ष सभी को फायदा होगा। सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए पूरी प्रक्रिया को डिजिटल किया गया है। एफआईआर की प्रक्रिया, एफआईआर के निर्णय सभी डिजिटल फॉर्म में होंगे। सामाजिक-आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से सभी नागरिक अलग-अलग स्थानों में रहते हैं। ऐसी स्थिति में दस्तावेज डिजिटल होने से फायदा मिलेगा।

पुलिस अधीक्षक श्री मोहित गर्ग ने कहा कि ई-एफआईआर के लिए फोन, ई-मेल, व्हाट्सएप के माध्यम से अपराध घटित होने की सूचना दे सकते हैं। अब इसके लिए जवाबदेही तय हो जाएगी। प्रार्थी को संबंधित थाने में जाकर हस्ताक्षर कर एफआईआर दर्ज करानी होगी। थाना प्रभारी या विवेचक को जांच की जरूरत लगने पर एसडीओपी या सीएसपी की लिखित अनुमति के बाद जांच होगी। झूठी शिकायत से बचने के लिए तीन दिवस में पुलिस अधिकारी जांच करेंगे तथा गंभीर मुद्दा होने पर एफआईआर दर्ज होगी तथा विधिवत प्रकरण की विवेचना की जाएगी।

दिव्यांगजनों के लिए ग्राम तुमड़ीबोड़ में विशेष शिविर का आयोजन

140 दिव्यांग हितग्राहियों ने कराया पंजीयन

राजनांदगांव। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल के निर्देशानुसार समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों का चिन्हांकन, मूल्यांकन, परीक्षण, राशन कार्ड सत्यापन, विशिष्ट पहचान पत्र बनाने एवं पेंशन हितग्राहियों का सत्यापन तथा विभागीय योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए 19 जून से 31 जुलाई 2024 तक सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक जनपद पंचायतवार विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत जनपद पंचायत डोंगरगांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तुमड़ीबोड़ में दिव्यांगजनों के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया।

शिविर में कुल 140 दिव्यांग हितग्राहियों को पंजीकृत किया गया। शिविर में अस्थिबाधित के लिए 95, दृष्टि बाधित के लिए 14, श्रवण बाधित के लिए 14, बहुविकलांग के लिए 6 एवं मानसिक दिव्यांग के लिए 11 आवेदन प्राप्त हुए। इस दौरान अंतर्राष्टीय नशा निवारण दिवस पर ग्रामीणों को नशा मुक्ति के लिए शपथ दिलाई गई। समाज कल्याण विभाग के कलाकारों द्वारा गीत-संगीत के माध्यम से जन मानस को नशा से दूर रहने का संदेश दिया गया। शिविर में जनपद सदस्य श्रीमती निर्मला सिन्हा, श्री विरेन्द्र साहू, श्री डाकेन्द्र चन्द्राकर एवं सरपंच श्री टीकम पटेल सहित अन्य पंचगण व जनप्रतिनिधि, जिला चिकित्सालय से मेडिकल बोर्ड से अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉ. अनिल महाकालकर, मनोरोग विशेषज्ञ डॉ. बीके बेनर्जी, मेडिसिन डॉ खुमान सिह मण्डावी, शिशुरोग विशेषज्ञ डॉ. हिमांसु नामदेव, समाज कल्याण विभाग से श्रीमती सुखमा चन्द्रवंशी, श्री बीके बघेल, श्रीमती मीना चन्द्रवंशी, श्रीमती कंचनकला मेश्राम, श्री निखिल साहू एवं जनपद पंचायत डोंगरगांव से श्री साहू, श्री ओम प्रकाश जैन, श्री विरेन्द्र तिवारी, श्री हिरालाल नेताम, श्री घनश्याम साहू, निर्मला साहू सहित बड़ी संख्या में दिव्यांगजन व ग्रामीणजन उपस्थित थे।

कार्यशाला में अधिकारियों कर्मचारियों को दिया गया राजस्व नियमों कार्यों का ज्ञान

सारंगढ़-बिलाईगढ़। कलेक्टर श्री धर्मेश कुमार साहू के निर्देश पर जिला कार्यालय के सभाकक्ष में राजस्व विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित किया गया। कार्यशाला के प्रथम दिवस को कलेक्टर श्री धर्मेश साहू के समक्ष डिप्टी कलेक्टर रायगढ़ श्री महेश शर्मा ने राजस्व न्यायालय की कार्य प्रक्रिया के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दिया। श्री शर्मा ने कहा कि भू-राजस्व संहिता की धाराओं को एवं सीपीसी की धाराओं को संयुक्त रुप से देखे जाने की आवश्यकता है क्योंकि बहुत से मामलों का भू-राजस्व संहिता में कोई प्रावधान नहीं है?। इसके पश्चात् बिलासपुर भू-अभिलेख शाखा के राजस्व निरीक्षक रमेश नायक एवं पीयूष दीवान के द्वारा भू-अभिलेख शाखा एवं डायवर्सन के संबंध में जानकारी दिया गया एवं राजस्व विभाग के पदाधिकारियों द्वारा पूछे गये प्रश्नों का समाधान किया गया। जांजगीर-चांपा कार्यालय से सहायक ग्रेड-2 शैलेन्द्र सिंह एवं नबीअहमद खान ने भू-आबंटन के संबंध में जानकारी दिया। इसी क्रम में बिलासपुर एवं रायगढ़ जिले से आए कर्मचारियों ने वाचक शाखा, नाजीर शाखा, प्रपत्र शाखा, शिकायत शाखा, बाढ़ राहत एवं सांख्यिकी शाखा एवं स्थापना शाखा से संबंधित प्रक्रियाओं के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दिए। इस अवसर पर एसडीएम सारंगढ़ अनिकेत साहू, डिप्टी कलेक्टर वर्षा बंसल, साथ ही राजस्व विभाग के समस्त अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण के लिए शिक्षा है सबसे अहम -लक्ष्मी राजवाड़े

महिला एवं बाल विकास मंत्री सूरजपुर के जिला स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव कार्यक्रम में हुई शामिल

सूरजपुर। विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण के लिए शिक्षा सबसे अहम है, यदि स्कूली शिक्षक लक्ष्य का निर्धारण करते हुए और संकल्प लेते हुए बच्चों को मन से पढ़ायेंगे तो निश्चित ही हमारे बच्चे प्रदेश के नाम को गौरवांवित करेंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने ये बात सूरजपुर के जिला स्तरीय शाला प्रवेश कार्यक्रम में कही। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित विद्यार्थी, पालक व शिक्षकों को उनकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद दिया और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के संदेश से कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके साथ ही उन्होंने उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए शिक्षा के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला।

कार्यक्रम में नवप्रवेशी विद्यार्थियों का स्वागत तिलक लगाकर और मिष्ठान खिलाकर किया गया। तत्पश्चात् सूरजपुर जिले अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले विकास के बिंदुओं से की गई। जिसका प्रदर्शन प्रोजेक्टर के माध्यम से किया गया। जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में किए गए नवाचार व गतिविधियों की संक्षिप्त झलकियों का प्रदर्शन किया गया। कस्तूरबा गांधी की छात्राओं द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। इसके साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित बच्चों के साथ-साथ उनके पालकों का भी सम्मान किया गया। इस अवसर पर जिले के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को भी सम्मानित किया गया और उन्हें इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट प्रदान करने की बात कही गई।कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों को सामग्री वितरण और बालिकाओं को सरस्वती योजना अंतर्गत सायकल प्रदान किया गया।

कार्यक्रम में पूर्व गृहमंत्री श्री रामसेवक पैकरा,श्री राजेश अग्रवाल,श्री अजय अग्रवाल, श्री बिहारी कुलदीप, श्री लवकेश पैकरा, श्री बिन्जु दासन एवं श्री राजेश्वर तिवारी,संभागायुक्त श्री गोविंद राम चुरेंद्र, कलेक्टर श्री रोहित व्यास, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती कमलेश नंदिनी साहू, जिला शिक्षा अधिकारी श्री रामललित पटेल, जिला मिशन समन्वयक श्री शशिकांत सिंह, सहायक संचालक शिक्षा श्री रविन्द्र देव सिंह एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

मल्टी स्पोटर्स ग्राउंड को दल्लीराजहरा में जल्द शुरू करने की मांग

कलेक्टर से मिला प्रतिनिधि मंडल

बालोद। खेलबो इंडिया द्वारा प्रस्तावित दल्लीराजहरा में मल्टी स्पोटर्स ग्राउंड की प्रक्रिया पूर्व के कई वर्षों से चल रही है। इसके लिए खेल मैदान की तलाश भी पूरी हो चुकी है। नक्शा, खसरा अनापत्ति सभी कार्य किये गए हैं। इस दौरान किसी के द्वारा मल्टी स्पोर्ट्स ग्राउंड लाटाबोड़ ले जाने के प्रयास की जानकारी मिलने पर राजहरा व्यापारी संघ के नेतृत्व में कलेक्टर से मिल खेलबो इंडिया द्वारा प्रस्तावित मल्टी स्पोर्ट्स ग्राउंड को दल्लीराजहरा में अतिशीघ्र प्रारंभ करने की मांग की गई।

ज्ञापन में कहा गया कि खेलबो इंडिया द्वारा मल्टी स्पोटर्स ग्राउंड प्रस्तावित किया गया है। जिसको लेकर विभिन्न अधिकारियों द्वारा दल्लीराजहरा में स्थल का निरीक्षण किया गया। परंतु ज्ञात हुआ है कि कुछ लोगों द्वारा इसे खेल नगरी दल्लीराजहरा से हटाकर लाटाबोड़ में स्थानांतरित करने का प्रयास किया जा रहा है जो कि जिले के सबसे बड़े नगर के साथ हमेशा से किये जा रहे सौतेले व्यवहार में एक है।

ज्ञात हो कि नगर व आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ी दल्लीराजहरा में सभी खेलों में प्रशिक्षण प्राप्त कर जिला, राज्य , राष्ट्रीय खेल में पदक प्राप्त करने के साथ अंतरराष्ट्रीय मैचों में भी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। दल्लीराजहरा को स्पोर्ट्स हब बनाने से भविष्य में और भी उत्कृष्ट खिलाड़ी बालोद जिले से सामने आएंगे। अतः इसे दल्लीराजहरा से दूसरे स्थान ले जाना नैतिक रूप से भी अनुचित है।

राज्य जूडो स्पर्धा में बालोद के खिलाड़ियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन

बालोद। छत्तीसगढ़ प्रदेश जूडो संघ के तत्वावधान में दुर्ग जिला जूडो संघ द्वारा 24वीं छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता गत दिनों कैंप 2 भिलाई में संपन्न हुई। इसमें बालोद जिला जूडो संघ की ओर से 7 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया।

ज्ञात हो कि इस प्रतियोगिता में 25 जिले के 350 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। प्रदेश जूडो संघ के आमसभा में सर्वसम्मति से - अरुण द्विवेदी को अध्यक्ष एवं शंभू सोनी को सचिव एवं आलोक मिश्रा को कोषाध्यक्ष चुना गया।

स्पर्धा में दल्ली राजहरा एवं बालोद जिला के खिलाड़ियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। दल्ली राजहरा मार्शल आर्ट क्लब के खिलाड़ी गगन सोनी अपने वजन ग्रुप में खेलते हुए रजत पदक प्राप्त किया।

बालोद जिला जूडो कोच के रूप में देवेंद्र भदोरिया, आर बी गहरवार श्रीकांत जनरल मैनेजर दल्ली राजहरा माइंस, नगर पालिका अध्यक्ष शिबू नायर, मार्शल आर्ट क्लब के अध्यक्ष अनिल खोब्रागड़े, हरबंस कौर, मिलन सिंग मराई एवं प्रणव शंकर साहू सहायक 2 1 कोच सहित खेल प्रेमी ने पदक विजेता खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं दी। यह समस्त जानकारी बालोद जिला सचिव एवं प्रदेश उपाध्यक्ष लखन कुमार साहू ने प्रदान की।

गिरिजा चंद्राकर बनीं खैरागढ़ नपा की कार्यवाहक अध्यक्ष

खैरागढ़। नगर पालिका परिषद खैरागढ़ में रिक्त अध्यक्ष पद पर गिरजा चंद्राकर को छत्तीसगढ़ शासन में नगर पालिका का अध्यक्ष नियुक्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं। भाजपा संगठन ने स्थानीय स्तर पर भाजपा पार्षदों की बैठक में एक नाम पर आम सहमति बनाकर गिरजा चंद्राकर का नाम प्रदेश संगठन को प्रस्तावित किया था।

मंगलवार को नगरी प्रशासन विभाग की अवर सचिव डॉ रितु वर्मा ने गिरजा चंद्राकर को अध्यक्ष नियुक्त करने आदेश जारी किए। अध्यक्ष की घोषणा होते ही नगर पालिका के सामने भाजपाइयों ने जमकर आतिशबाजी कर खुशियां मनाई। अमलीपाड़ा वार्ड से दूसरी बार निर्वाचित पार्षद गिरजा चंद्राकर के अध्यक्ष बनने पर आमलीपारा में भी आतिशबाजी कर वह मिठाई वितरण कर अपनी खुशियों का इजहार किया।

अध्यक्ष पद ग्रहण करते ही गिरिजा ने कहा कि मुझे जो जिम्मेदारी सौंप गई है उसका मैं पूरे निष्ठा और ईमानदारी से पूरा करूंगी शहर में विकास कार्यों को मूर्ति रूप दिया जाएगा, वहीं लंबित प्रस्तावों आवेदनों व मांगों पर त्वरित कार्रवाई कर लोगों को रहा टी देने का प्रयास होगा। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करने शहर की साफ सफाई व्यवस्था बिजली पानी व्यवस्था दुरुस्त करने प्राथमिकता के साथ कार्य किए जाएंगे।

इस अवसर पर जिला भाजपा अध्यक्ष घुम्मन साहू युवा मोर्चा अध्यक्ष आयश सिंह, विकेश गुप्ता रामादा रजक शौरयादित्य सिंह आलोक श्रीवास सहित भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे।

जनसहभागिता से चलाया गया शालेय स्वच्छता अभियान

खैरागढ़। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया एक राष्ट्रीय अभियान है जिसका उद्देश्य अपने आस-पास के परिवेश, निवास, सार्वजनिक स्थल को साफ सुथरा रखना है।

इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाने हेतु कलेक्टर चन्द्रकांत वर्मा के मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देश में शिक्षा विभाग एवं पंचायत विभाग के द्वारा जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई के प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शाला परिसर में स्कूल खुलने के पूर्व जनभागीदारी से स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है।

शाला के प्रधान पाठक, प्राचार्य, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सरपंच, समूह की महिलाएँ एवं ग्रामवासियों के द्वारा शाला परिसर में सफाई के साथ साथ घास फुस भी निकाले जा रहे हैं। शौचालय की साफ सफाई, रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की मरम्मत एवं शाला की पुताई भी की जा रही है। इससे पूर्व कलेक्टर चंद्रकांत वर्मा द्वारा अपर कलेक्टर प्रेमकुमार पटेल, जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी सहित प्राचार्य प्रधान पाठकों की बैठक लेकर शाला खुलने से पूर्व शाला परिसर की साफ सफाई के निर्देश दिये गए थे द्य उन्होंने इस अवसर पर प्राचार्य को संबोधित करते हुए कहा कि शाला एवं परिसर की साफ सफाई छात्रों अध्यापन के लिए आवश्यक है। हमारे जीवन में स्वच्छता बहुत जरूरी है। यदि शाला के आस पास का वातावरण स्वच्छ और साफ सुथरा रहेगा तो बच्चों का मन शाला में रहकर अध्ययन में लगेगा। शालाओ की साफ सफाई अभियान को जिला शिक्षा अधिकारी लाल जी द्विवेदी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, नीलम राजपूत व रमेंद्र डड़सेना, संकुल समन्वयक निरंतर गति प्रदान करते हुए सतत मोनिटरिंग कर रहे है। इस कार्य में पंचायत विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और आम नागरिकों का भरपूर सहयोग मिल रहा है।

कलेक्टर-एसपी ने ली जिले की कानून व्यवस्था की समीक्षा

खैरागढ़। कलेक्टर चंद्रकांत वर्मा और पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल ने राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक लेकर कानून व्यवस्था के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए।

बैठक में कलेक्टर ने कई जगहों की घटनाओं का जिक्र करते कहा की सभी राजस्व एवं पुलिस अधिकारी सचेत रहे। कहीं भी किसी भी प्रकार के अप्रिय घटना की आशंका होने पर तत्काल सूचना दें। उन्होंने कहा कि जिले में कहीं भी अप्रिय घटना की स्थिति निर्मित नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सूचना तंत्र को मजबूत कर कार्य करें। किसी तरह की अप्रिय घटना होने पर तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करें। ताकि समय पर कार्रवाई की जा सकें। उन्होंने सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी प्रसारित करने वालों पर निगरानी रखने को कहा। उन्होंने कहा कि गंडई में आयोजित होने वाले शिव महापुराण हेतु भीड़ को नियंत्रित रखने विशेष व्यवस्था रखे। उन्होंने राजस्व एवं पुलिस अधिकारीओ को

आपसी सामंजस्य स्थापित कर टीम वर्क के साथ काम करने कहा। इसके साथ ही समय समय पर थाना एवं अनुविभागीय स्तर पर संयुक्त बैठक आयोजित भी करें। कलेक्टर ने राजस्वी एवं पुलिस अधिकारियों को शांति समिति की बैठक भी आयोजित करने के भी निर्देश दिए, जिससे की स्थानीय स्तर की समस्याओ को जान सके।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक समाज के धार्मिक स्थलों को चिन्हित कर, समाज प्रमुखों से सतत सम्पर्क करते हुए समाज प्रमुखों की बैठक ले। उन्होंने कहा कि जिले में धार्मिक महत्त्व के स्थलों को चिन्हांकित करे ताकि सीसीटीवी कैमरा लगा के निगरानी की जा सके।

उन्होंने धार्मिक स्थलों पर छेड़छड करने वाले असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिये। उन्होंने राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों से कहा की आप के कार्यालय में कोई आम नागरिक समस्या ले के आए उनकी समस्या को विनम्र पूर्वक सुने। इसी प्रकार कलेक्टर वर्मा ने हिंसा एवं प्रदर्शन के संभावित कारणों एवं उसके रोकथाम संबंधित उपायों पर विस्तार से चर्चा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

पुलिस अधिक्षक त्रिलोक बंसल ने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था का कड़ाई से पालन हो, शांति व्यवस्था बना के रखे, राजस्व एवं पुलिस अधिकारी आपसी सामंजस्य के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि किसी भी छोटी सी छोटी घटनाओं को उच्च अधिकारियों को सूचित करे। ताकि कोई बड़ी घटना का रूप न ले। उन्होंने सभी अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए पूरी निष्ट के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर प्रेम कुमार पटेल, एसडीएम छुईखदान-गंडई रेणुका रात्रे, एसडीएम खैरागढ़ टंकेश्वर प्रसाद साहू सहित राजस्व व पुलिस के अधिकारी उपस्थित थे।

कलेक्टर ने शाला प्रवेशोत्सव पर स्कूल के दिनों को किया याद

बेमेतरा। नए शिक्षा सत्र की शुरुआत के साथ ही जिले के समस्त स्कूलों में शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन किया गया।

कलेक्टर रणबीर शर्मा ने बैजलपुर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला में आयोजित शाला प्रवेशोत्सव में भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक दिपेश साहू रहे। विधायक व कलेक्टर ने बच्चों का तिलक लगाकर और मिठाई खिलाकर स्वागत किया।

उन्होंने निःशुल्क किताब और गणवेश भेंट किए। कलेक्टर ने अपने स्कूलों के दिनों को याद किया और एक बच्ची से राष्ट्रपति का नाम पूछा। वहीं एक ने कविता सुनाई। उन्होंने परिसर में पौधरोपण भी किया। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी कमल बंजारे, असिस्टेंट कमिश्नर ट्राइबल आरएस टंडन, खाद्य अधिकारी गणेश कुर्रे मौजूद रहे।

किसानों से खरीदी उपज, फिर नहीं किया भुगतान, अपराध दर्ज

बेमेतरा। किसानों से उपज लेकर भुगतान नहीं करने वाले दो आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने शिकायत के बाद अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार धान खरीदने के बाद किसानों को चूना लगाने वाले आरोपी लीला राम पंचभैया व जित्तू साहू नेवसा द्वारा गोपालभयना, रिसामती के किसानों से अधिक रेट में धान खरीदी कर धोखाधड़ी किए जाने की शिकायत की गई थी।

बताया गया कि बीते जनवरी 2024 को जित्तू साहू ने प्रार्थी को बताया कि ग्राम पंचभैया निवासी लीला राम साहू निवासी द्वारा 3100 रूपये के भाव से धान खरीदने और 45 दिन के बाद में 3100 रूपये के भाव से भुगतान करने की बात कही गई थी। साथ ही जित्तू साहू ने स्वयं को लीला राम का मुंशी बताकर धान खरीदी करने की बात कही थी। इसके बाद 21 जनवरी को मनीष ने ग्राम नेक्सा में 165 बोरी धान जित्तू साहू को बेचा था। तयभाव के अनुसार 204600 रूपये का पर्ची काट कर दिया। 30 जनवरी को जित्तू साहू ने प्रार्थी मनीष से दोबारा धान खरीदा जिसमें उससे 300 बोरी धान खरीदा गया था जिसके लिए 3,72,000 रूपये का पर्ची काट कर दिया।

इसी तरह 4 फरवरी को 404 बोरी धान, कीमत 500960 रूपया। 27 फरवरी को 157 बोरा राहर 13000 रूपये की दर से खरीदा था जिसके लिए 1026740 रूपये में खरीदने का पर्ची काट कर दिया। जित्तू साहू ने मनीष से धान व अरहर खरीदा था जिसकी की कुल राशि 2104300 लेना था। जित्तू साहू रकम देने में टाल मटोल करता रहा तथा उसे बताया गया कि उसने दोनों उपज को ग्राम पंचभैया निवासी लीलाराम के पास बेच दिया है पर उसे भूगतान नहीं किया है। प्रार्थी ने शिकायत की थी, जिसमें जित्तू साहू, लीलाराम साहू ने छल कपट, धोखाधड़ी कर धान व अरहर खरीदा है। आरोपी द्वारा किसानों को चेक दिया गया था जो पूर्व ही बाउंस हो गया था।

अन्य गांव के किसानों से भी उपज ली पर भुगतान नहीं किया

शिकायत पत्र के अनुसार अनाज खरीदने वाले दोनों आरोपियों ने मनीष साहू के अलावा ग्राम नेवसा के भुवन साहू, लेखा राम साह, कुमार साहू, दुर्जन साहू, शेषु साहू से भी अधिक दाम पर धान व अरहर खरीदा गया। वहीं ग्राम गोपालभैना व रिसामली के किसानों से भी उपज खरीदकर धोखाधड़ी कर बेईमानी किया जाना बताया गया है। आरोपी के खिलाफ धारा 420 व 34 भादवि के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

लोगों को पानी के लिए करनी पड़ रही मशक्कत

बेमेतर्रा। शहर के लगभग सभी वार्डों में जलसंकट गहराने लगा है। आलम यह है कि वार्डों में टैंकर से पानी की सप्लाई की जा रही है। शहरवासी गर्मी की शुरुआत में पानी के लिए तरस रहे हैं। मीठे पानी की योजना पर करीब 25 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। बावजूद शहर वासियों को मीठा पानी नहीं मिल रहा है।

जानकारी के अनुसार पीएचई विभाग ने मीठे पानी की योजना को क्रियान्वन के लिए नगर पालिका को हैंडओवर करने की बात कही है, लेकिन नगर पालिका इंकार कर रहा है। फिर भी योजना का संचालन नगर पालिका के द्वारा किया जा रहा है।

शहरवासियों ने बताया जिस जगह पर नल चल रहा है। वहां पर लाइन लगाकर पानी भरने को मजबूर है। घरों तक पानी पहुंचाने में काफी समस्या होती है। परिवार को सुबह और शाम में पानी भरने को लेकर संघर्ष करना पड़ रहा है।

शहरी जल आवर्धन योजना पर 25 करोड रुपए खर्च होने के बावजूद शहरवासियों को मीठा पानी नहीं मिल रहा है। इस संबंध में संबंधित नगर पालिका व पीएचई विभाग मामला एक दूसरे पर डालकर पल्ला झाड़ रहे हैं। योजना की शुरुआत से लेकर 10 साल तक कई वार्ड में पाइप लाइन का विस्तार नहीं हुआ हैं। मीठे पानी की योजना से सही तरीके से शहरवासियों को जलापूर्ति होने की स्थिति में हर माह वाटर पंप के संचालन में आ रहे हैं, लाखों रुपए बिजली बिल की बचत होगी

शहर के लोगों को जलापूर्ति के लिए ढाई सौ पावर पंप है। वाटर लेवल गिरने के कारण पावर पंप जवाब देने लगे हैं। मानसून में विलंब होने के कारण शहर में करीब 12 दिनों से पानी नहीं गिरा है। पावर पंपों से पानी आपूर्ति में बाधा आ रही है। लगातार वाटर लेवल गिरता जा रहा है। समस्या के निराकरण के लिए आमजनों का पालिका अधिकारी को फोन लगाने पर कॉल रिसीव नहीं करते।

पानी आपूर्ति के समय में एक घंटे की कटौती

जानकारी के अनुसार वाटर लेवल गिरने के बाद से नगर पालिका प्रशासन की ओर से पानी आपूर्ति के समय सीमा में 1 घंटे की कटौती की गई है ताकि आने वाले दिनों में सुचारू रूप से शहर पानी की आपूर्ति की जा सके। दिनों दिन जल संकट गहराने के साथ लोगों की समस्याएं बढ़ती जा रही है।

कोमल साहू की संदेहास्पद मौत, निष्पक्ष जांच के लिए डिप्टी सीएम शर्मा के निर्देश पर एसआईटी गठित

कवर्धा। उप-मुख्यमंत्री व गृह मंत्री विजय शर्मा ने ग्राम-बिरकोना, थाना-पिपरिया, जिला-कबीरधाम निवासी मृतक कोमल साहू पिता स्व.प्रेमलाल साहू की संदेहास्पद मृत्यु की निष्पक्ष उच्च-स्तरीय जांच के लिए एस.आई.टी. गठित किए जाने के निर्देश अपर मुख्य सचिव को दिए थे।

गृहमंत्री ने प्रकरण की विशिष्टता एवं संवेदनशीलता के दृष्टिगत अनुसंधान हेतु पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में 6 सदस्यीय विशिष्ट जांच दल तत्काल गठित करने हेतु निर्देशित किया था जिस पर जांच कमेटी गठित किया गया है।जाँच समिति को त्वरित जाँच करने निर्देशित किया गया है।

एसआईटी में निम्न अधिकारी रहेंगे- ामकृष्ण साहू, पुलिस अधीक्षक, जिला-बेमेतरा, नेहा पाण्डेय, अति. पुलिस अधीक्षक, खैरागढ़, मोहन पटेल, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, प्रभारी सीन ऑफ काईम यूनिट, जिला-दुर्ग, तनुप्रिया ठाकुर, उपुअ (अजाक), जिला-राजनांदगांव, विजय मिश्रा, निरीक्षक जिला-राजनांदगांव, मयंक मिश्रा, उप निरीक्षक जिला-बेमेतरा।

धान खरीदी में अनियमितता, कोदवागोड़ान के धान उपार्जन केन्द्र प्रभारी पर एफआईआर

धान उठाव और भौतिक सत्यापन में गड़बड़ी, 69 धान खरीदी केन्द्र को नोटिस

कवर्धा। कलेक्टर जनमेजय महोबे के निर्देश पर खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में धान खरीदी में अनियमितता बरतने पर उप पंजीयक सहकारी सेवा संस्था ने कोदवागोड़ान के धान उपार्जन केन्द्र प्रभारी चंद्रकुमार चंद्राकर के विरूद्ध बड़ी कार्रवाई की है। कोदवागोड़ान के धान उपार्जन केन्द्र में भौतिक सत्यापन करने पर 4 हजार 160 क्विंटल धान कम पाई गई, जिसकी लागत 90 लाख 81 हजार 829 रूपए आंकी गई।

भौतिक सत्यापन के दौरान अनियमितता पाए जाने पर कोदवागोड़ान धान उपार्जन केन्द्र प्रभारी के खिलाफ कुकदूर थाना में एफआईआर पंजीबद्ध किया गया है और आगे निलंबन, बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर श्री महोबे ने खाद विभाग, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक और उप पंजीयक सहकारी सेवा संस्था की संयुक्त दल को जिले में संचालित सभी 108 धान खरीदी केन्द्रों का निरीक्षण कर भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए थे। संयुक्त टीम द्वारा निरीक्षण कर धान के उठाव, भौतिक सत्यापन एवं सुरक्षा का जांच किया गया। इसमें गड़बडी पाए जाने पर 69 धान खरीदी केन्द्र को नोटिस जारी किया गया है। जांच के दौरान जिस भी उपार्जन केन्द्र में धान खरीदी में अनियमितता पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

उप पंजीयक सहकारी सेवा संस्था सतीष पाटले ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर संयुक्त टीम द्वारा ग्राम कोदवागोड़ान धान उपार्जन केन्द्र में निरीक्षण कर भौतिक सत्यापन और धान के उठाव का जांच किया गया। जांच में कोदवागोड़ान धान उपार्जन केन्द्र में अब तक 10 हजार 562 मी. टन धान की खरीदी की गई है। इसमें 10 हजार 97 मी. टन धान का उठाव किया गया है तथा शेष स्टॉक ऑनलाईन 465 मी. टन पाई गई।

बाहपानी दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को अनुग्रह चेक दिया भावना ने

कवधा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय विगत 20 मई को कबीरधाम जिले के विकासखंड पंडरिया के ग्राम बाहपानी में हुई सडक़ दुर्घटना में मृतकों के दशगात्र में शामिल हुए थे।

मृतकों के परिजन को प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए एवं घायलों को प्रति व्यक्ति 50 हजार रुपए आर्थिक सहायता प्रदाय करने की घोषणा की थी। इसके लिए सडक़ दुर्घटना में मृतकों के परिजनों तथा घायलों सहित 35 अनुदानग्रहिताओं को अपने स्वेच्छानुदान मद से 1 करोड़ 3 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की थी।

पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने ग्राम सेमरहा में मृतकों के परिजनों तथा घायलों के घर पहुंचकर 19 मृतकों के परिजनों को 5 लाख रूपए के मान से 95 लाख रूपए तथा इस घटना में 16 घायलों को 50-50 हजार रूपए के मान से कुल 8 लाख रूपए का चेक प्रदान किया। इस अवसर पर अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार सहित क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि राज्य के संवेदनशील मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कबीरधाम जिले के विकासखंड पंडरिया के ग्राम बाहपानी में 20 मई को हुई सडक़ दुर्घटना में मृतकों के परिजनों तथा घायलों सहित 35 अनुदानग्रहिताओं को अपने स्वेच्छानुदान मद से कुल 1 करोड़ 3 लाख की राशि स्वीकृत की थी। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रूपए तथा घायलों को 50-50 हजार रूपए के मान से सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

मुख्यमंत्री ने कबीरधाम जिले के ग्राम बाहपानी की सडक़ दुर्घटना में मृतक प्यारी बाई, कुमारी सोनम बाई धुर्वे, धनैया बाई धुर्वे, सिरदारी राम धुर्वे, कुमारी किरण, शांति बाई, तिको बाई, मीला बाई, जनिया बाई, मुंगिया बाई, झंगलो बाई धुर्वे, सियाबाई, पैंटोरिन बाई मेरावी, बिस्मत बाई मेरवी, लीला बाई, परसदिया देवी, भारती बाई, कुनती बाई, धानबाई धुर्वे के परिजन को 5-5 लाख रूपए की राशि तथा 16 घायलों ममता, मुन्नी बाई, गुलाब सिंह, दयाराम, शिवनाथ, महावीर, कार्तिक, धन्नू, इन्द्राणी, जोधीराम, अनिल, फूलचंद, मानसिंह, श्रीराम, रम्हउ, बजरू को 50-50 हजार की सहायता राशि मंजूर की है।

सिटी कोतवाली स्थित मल्टीलेवल पार्किंग की 46 दुकानों का आवंटन रद्द

सुरक्षा मानक व आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए फिर करनी होगी नीलामी

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सिटी कोतवाली परिसर में बनाए जा रहे मल्टीलेवल पार्किंग की 46 दुकानों का आवंटन रद्द कर दिया है। अब इन दुकानों की नीलामी फायर एंड सेफ्टी ऑडिट करने तथा आरक्षण नियमों का पालन करने के बाद होगी।

हाईकोर्ट में बिलासपुर निवासी आदिवासी वर्ग के कार्यकर्ता नंदकिशोर राज व व्यवसायी महेश दुबे की ओर से इसे लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया है।

याचिकाकर्ताओं के वकील सुदीप

श्रीवास्तव ने सुनवाई के दौरान बताया गया कि पहले इस बिल्डिंग में दुकानें प्रस्तावित नहीं थी। बाद में पार्किंग के प्रथम फ्लोर को दुकानों में परिवर्तित करने के लिए वेंटीलेशन समाप्त कर दिया, जिससे आगजनी की घटना में बचाव नहीं हो पाएगा। स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने पार्किंग पर आने वाले खर्च की भरपाई के लिए यहां दुकान बनाने का निर्णय लिया था।

हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य, केंद्र सरकार या उसका उपक्रम पैसे की कमी की दलील देकर आरक्षण के नियम की अवहेलना कर कोई कार्य नहीं कर सकता है। फैसले में न्याय के उस सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया जिसमें कहा गया है कि यदि कोई नियम या अधिनियम किसी कार्य को एक निश्चित तरीके से करने की बात कहता है, तो वह कार्य केवल उसी तरह किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। यदि दुकानों का आवंटन के लिए 1994 का नियम लागू है तो वह स्मार्ट सिटी लिमिटेड पर भी लागू होगा क्योंकि उसकी पैरेंट बॉडी नगर निगम है और राज्य सरकार इसमें अंशधारक है। दोनों ही संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य की परिभाषा में आते हैं जिन पर इस नियम को लागू करने का दायित्व है।

हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब स्मार्ट सिटी लिमिटेड और नगर निगम को इन दुकानों को नए सिरे से आवंटन करने के लिए आरक्षण नियमों का पालन करते हुए पुन: नीलामी करनी होगी। इसके तहत एससी, एसटी, ओबीसी के अलावा महिला, दिव्यांग, स्वतंत्रता सेनानी, पूर्व सैनिक आदि कई श्रेणियों को अवसर देना होगा। यह नीलामी बिल्डिंग का फायर और सेफ्टी ऑडिट करने के बाद की जाएगी।

राज्य सरकार तथा स्मार्ट सिटी की ओर से महाधिवक्ता प्रफुल्ल भारत और केंद्र सरकार की ओर से डिप्टी सॉलिसिटर जनरल रमाकांत मिश्रा ने मामले में बहस की।

युगल किशोर ने अपेक्स बैंक में महाप्रबंधक का पदभार ग्रहण किया

रायपुर। सहकारिता विभाग द्वारा जारी आदेश के परिपालन में श्री युगल किशोर ने छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक (अपेक्स बैंक) में महाप्रबंधक का पदभार ग्रहण कर लिया है। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा सहकारिता विभाग के उपायुक्त श्री युगल किशोर को प्रतिनियुक्ति पर अपेक्स बैंक में महाप्रबंधक के पद पर पदस्थ किया गया है।

मंत्री तोखन साहू का स्वागत

बिलासपुर। भारतीय जनता पार्टी बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र कोटा विधानसभा के कार्यकर्ता माना एयरपोर्ट रायपुर, तोखन साहू आवास शहरी विकास केंद्रीय राज्य मंत्री का छत्तीसगढ़ प्रथम आगमन पर भव्य स्वागत एयरपोर्ट रायपुर में किया साथ में, भारतीय जनता पार्टी प्रदेशाध्यक्ष किरण देव, अरुण साव लोक निर्माण मंत्री पीएचई मंत्री नगरी प्रशासन सभी किया और कोटा नगर पंचायत आने का निमंत्रण दिया और शहर विकास के लिए सहयोग हेतु आग्रह किया।

वेंकट लाल अग्रवाल जिला संयोजक सांस्कृतिक प्रकोष्ठ सियाराम साहू पूर्व विधायक, अरुण सिंह चौहान जिला पंचायत अध्यक्ष, प्रदीप कौशिक नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि कोटा, नरेंद्र बाबा गोस्वामी विधि प्रकोष्ठ प्रमुख गायत्री साहू जिला महामंत्री महिला मोर्चा लखन साहू पार्षद अमरनाथ साहू पार्षद, छोटा पार्षद,नरेंद्र पालके, गोविंद साहू भाजपा गिरिराज गोस्वामी, विकास सिंह ठाकुर, बैकुंठ नाथ जायसवाल, गणेश राम साहू, सुशांत साहू भाजपा नेता सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे।

कलेक्टर ने ग्रामीण अस्पताल व सोसायटी का किया निरीक्षण

बिलासपुर। बिलासपुर जिला कलेक्टर अवनीश शरण ने गुरुवार को कोटा के शिवतराई में पीएम जनमन योजना की समीक्षा के बाद शासकीय योजनाओं के मैदानी हालात का जायजा लेने करगीकला और पीपरतराई का आकस्मिक दौरा किया।

उन्होंने इन ग्रामों में स्वास्थ्य केंद्र और खाद बीज वितरण सोसायटी का निरीक्षण किया। हितग्राहियों से चर्चा कर सुविधाओं की जानकारी ली। करगीकला पीएचसी में दवाई वितरण कक्ष में एक्सपायरी दवा मिलने पर फार्मासिस्ट मुकेश पोर्ते और सेक्टर सुपरवाइजर को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। ग्रामीण चिकित्सा सहायक का एक इंक्रीमेंट रोकने का भी निर्देश दिया।

कलेक्टर ने करगी कला पीएचसी में दवाई वितरण कक्ष, ओपीडी, प्रसव कक्ष, पुरुष वार्ड सहित पूरे अस्पताल का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों से सहानुभूति रखते हुए सौहार्दपूर्ण व्यवहार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। कलेक्टर ने प्रसव के संबंध में जानकारी ली। डॉक्टर ने बताया कि यहां हर माह औसतन 10 प्रसव होता है। कलेक्टर ने सभी को निर्देश दिए कि समय पर उपस्थित होकर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराए। उन्होंने बीएमओ को सभी पीएचसी का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने पीपरतराई उपस्वास्थ्य केंद्र का भी जायजा लिया। यहां ग्रामीणों से चर्चा कर स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य सुविधाओं पर संतुष्टि जाहिर की।

खेती किसानी के मौसम में कलेक्टर आज करगीखुर्द और पीपरतराई सोसायटी का भी निरीक्षण करने पहुंचे। यहां उन्होंने किसानों से चर्चा कर खाद बीज की उपलब्धता की जानकारी ली।

बिलासपुर रेंज के 187 कर्मचारियों ने लिया फोटो, वीडियोग्राफी, फिंगर प्रिंट लेने का प्रशिक्षण

एक जुलाई से सात साल से अधिक की सजा वाले सभी मामलों की जांच एक्सपर्ट टीम करेगी

बिलासपुर। एक जुलाई को पूरे देश में लागू हो रहे नए कानून में किए गए प्रावधान के अनुसार सात साल या उससे अधिक सजा वाले मामलों में जांच का काम न्याय दल को दिया जाएगा। इसमें विवेचक के अलावा फोटो, वीडियो, फिंगरप्रिंट आदि में एक्सपर्ट लोग शामिल रहेंगे। कोर्ट में भौतिक साक्ष्य के आधार पर आरोप सिद्ध करना होगा। संदेही या दोष सिद्ध मुजरिम का फिंगरप्रिंट, फोटो, वीडियो का डेटाबेस भी तैयार कर डिजिटल फॉर्मेट में सुरक्षित रखा जाएगा।

उक्त जानकारी एडिशनल एसपी अर्चना झा और नोडल अधिकारी मंजूलता केरकेट्टा ने रेंज के पुलिस कर्मचारियों को प्रशिक्षण के दौरान दी। पांच दिन तक चले इस प्रशिक्षण में 187 प्रतिभागी शामिल हुए, जो रेंज के आईजी डॉ. संजीव शुक्ला व एसपी रजनेश सिंह के निर्देशन में दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि प्रत्येक अपराध का उद्देश्य सिद्ध करने के लिए भौतिक साक्ष्य महत्वपूर्ण होगा। प्राथमिकता और सावधानी से किया जाना है। रेंज व जिला स्तर पर फिंगरप्रिंट, फोटो वीडियो ग्राफर की कमी के कारण थाना स्तर के कर्मचारी इसे संपादित करेंगे। प्रशिक्षण में प्रत्येक थाने से दो-दो कर्मचारी शामिल थे।

पुलिस मुख्यालय से उक्त प्रशिक्षण के लिए फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट निरीक्षक अजय साहू अंजली मिंज तथा एएसआई विनीता शर्मा को प्रशिक्षक नियुक्त किया गया था।

रेंज फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट निरीक्षक विद्या जौहर और पीएचक्यू से नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आईडेंटिफिकेशन सिस्टम (एनएएफआईएस) की टीम ने प्रशिक्षण दिया और नमूना घटना स्थल तैयार कर अभ्यास कराया।

सदगुरु कबीर प्राकट्य उत्सव में शामिल हुए डिप्टी सीएम साव

दुग। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने रविवार को दुर्ग जिले के अहिवारा में 2 करोड़ 68 लाख 94 हजार रुपये लागत के 41 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। इसमें 17 लाख 84 हजार रुपये लागत से नवनिर्मित नगर पालिका परिषद भवन अतिरिक्त के कक्ष का लोकार्पण तथा नगर पालिका के विभिन्न वार्डो में 2 करोड़ 51 लाख 10 हजार रूपए लागत के 40 निर्माण कार्यों का भूमिपूजन शामिल है।

उपमुख्यमंत्री श्री साव ने अपने कर कमलों से हितग्राहियों को राशि का चेक भी प्रदान किया।

तत्पश्चात् कबीर भवन में आयोजित श्री सदगुरू कबीर प्रागट्य उत्सव को मुख्य अतिथि की आसन्दी से सम्बोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि अहिवारा से मेरा बचपन से नाता रहा है।

भारत माता की गर्भ से बड़े-बड़े संत महात्मा हुए है। इनमें से एक संत कबीर भी है। उन्होंने कहा कि कबीर की वाणी में जीवन दर्शन मिलता है। कबीर की वाणी को घर-घर तक पहुंचाये और जीवन में आत्मसात करें। यह परिसर कबीर के वाणी का प्रचार प्रसार का माध्यम बने।

भावनाओं के अनुरूप काम करें विद्यार्थी- विजय बघेल

शासकीय उमावि वैशाली नगर में जिला स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव

दुर्ग। उल्लास और उमंग के साथ शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वैशाली नगर में आयोजित जिला स्तरीय प्रवेशोत्सव कार्यक्रम को मुख्य अतिथि की आसंदी से सम्बोधित करते हुए सांसद विजय बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंशानुरूप विकसित भारत बनाने की पहल में देश के हर नागरिक को शिक्षित होना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति निरक्षर न रहे, इसके लिए सरकार की पहल जारी है। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों से कहा वे निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिए सद्भावना पूर्वक सेवाभाव से सहयोग करेंगे। सांसद श्री बघेल ने कहा कि सरकार की बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान की यह देन है कि आज बेटियां शिक्षा के साथ-साथ हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है।

उन्होंने कहा कि विद्यार्थी अपने माता-पिता की भावनाओं के अनुरूप काम करें। साथ ही गुरुजनों के प्रति हमेशा सम्मान का भाव रखे।

सांसद विजय बघेल के मुख्य आतिथ्य में तथा विधायक अहिवारा डोमन लाल कोर्सेवाड़ा, विधायक वैशालीनगर रिकेश सेन और विधायक दुर्ग ग्रामीण, ललित चंद्राकर की उपस्थिति में शुक्रवार को जिला स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव कार्यक्रम हुआ। जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी भी सम्मिलित हुई। मुख्य अतिथि सांसद श्री बघेल एवं अन्य अतिथियों ने आंगनबाड़ी केंद्र खुर्सीपार के बच्चों को तिलक लगाकर मिठाई खिलाई। इसी कड़ी में विद्यालय के पहली, छठवीं, नवमीं और ग्यारहवीं कक्षा के नवप्रवेशी विद्यार्थियों को भी तिलक लगाकर गणवेश और पाठ्यपुस्तक भेंट कर स्वागत किया गया।

इस अवसर पर अतिथियों द्वारा विद्यालय की 10 छात्राओं को सायकल भी वितरित की गई।

एसीबी की प्रदेश में तेज कार्यवाही

करप्शन के खिलाफ एक्शन में छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार

ढाई महीने में एसडीएम, जेडी, ईई, एसआई समेत 21 रिश्वतखोर गए जेल

रायपुर। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी को फ्री हैंड दिया, उसके नतीजे आने लगे हैं। एक अप्रैल से लेकर अभी तक 14 मामलों में 22 अधिकारी, कर्मचारी जेल जा चुके हैं। इनमें एसडीएम से लेकर ज्वाइंट डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, एसआई, एएसआई, पटवारी शामिल हैं। कई बार तो ऐसा हुआ है कि एक दिन में तीन-तीन, चार-चार सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत लेते एसीबी ने धर दबोचा। जाहिर है, रंगे हाथ रिश्वत लेते पकड़े जाने पर कोई से जमानत नहीं। तीन महीने जेल में काटने के बाद ही बेल मिलती है। वो भी अगर तीन महीने में अगर चार्ज शीट दाखिल नहीं हुआ तो।

पहले ही भाषण में संकेत दिया था सीएम ने

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शपथ लेने के बाद अपने पहले ही भाषण में छत्तीसगढ़ में गुड गवर्नेंस पर जोर देते हुए कहा था कि उनकी सरकार भ्रष्ट अफसरों, कर्मचारियों को नहीं बख्शेगी। आम लोगों से रिश्वत के लिए परेशान करने वाले लोगों से उनकी सरकार सख्ती से पेश आएगी। इसके बाद एसीबी द्वारा लगातार कार्रवाइयों का दौर जारी है।

अमरेश मिश्रा के एसीबी चीफ बनने के बाद कार्रवाई तेज

30 मार्च को डीएम अवस्थी की संविदा नियुक्ति समाप्त होने के बाद आईपीएस अमरेश मिश्रा को एसीबी और ईओडब्लू की कमान सौंपी गई थी। 1 अप्रैल से अमरेश मिश्रा ने जांच एजेंसी का काम संभाला था। इसके बाद कुछ दिन उन्हें एजेंसी को समझने में लगा। 15 अप्रैल के बाद एसीबी ने भ्रष्ट अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। और करीब ढाई महीने में 14 कार्रवाइयों में 22 लोग जेल जा चुके हैं। इनमें एसडीएम, ज्वाइंट डायरेक्टर, ईई जैसे शीर्ष अधिकारी शामिल हैं। तो वहीं एसीबी टीम ने एसआई और एएसआई को भी नहीं छोड़ा। दिलचस्प यह है कि पिछले पांच साल में एसीजी ने जितनी कार्रवाइयां नहीं की, उससे कई गुना ढाई महीने में हो चुकी है। एसीबी के सूत्रों की मानें तो पिछले पांच साल में रिश्वत लेते ट्रेप होने वाले मुलाजिमों की संख्या दर्जन भर भी नहीं पहुंच पाई।

एसडीएम को जेल

छत्तीसगढ़ में इससे पहले एसडीएम भागीरथी खाण्डे को रिश्वत लेते पकड़े जाने के बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। रेवेन्यू और मजिस्ट्रेट का पावर होने की वजह से एसडीएम के तार रसूखदार लोगों से लेकर सरकार में भी उपर लेवल तक जुड़े होते हैं। इसलिए, छत्तीसगढ़ में अभी तक पटवारी के आसपास ही कार्रवाइयां सीमित होती थी।

एसीबी को फ्री हैंड

बताते हैं, गुड गवर्नेंस के लिए सरकार ने ईओडब्लू और एसीबी को फ्री हैंड दे दिया है। सरकार ने भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ कोई मरौव्त न करते हुए कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। हालांकि कहने के लिए ईओडब्लू और एसीबी राज्य सरकार की स्वतंत्र जांच एजेंसी है। उसे अपने हिसाब से भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। मगर ये सिर्फ कहने के लिए है। बिना सरकार से इजाजत लिए एसीबी का कोई कार्रवाई नहीं करती। राज्य सरकारें ऐसा चाहती भी नहीं कि ईओडब्लू और एसीबी ताकतवर होकर कार्रवाइयां करें। अलबत्ता, राजस्थान में ईओडब्लू और एसीबी इतना सक्षम है कि आईएएस, आईपीएस अधिकारियों को गिरफ्तार कर लेती है। मगर छत्तीसगढ़ में पटवारी, डिप्टी रेंजर से उपर नहीं उठ पाते। पिछले पांच साल में ईओडब्लू, एसीबी के हाथ-पैर बांध दिए गए थे। आलम यह रहा कि पांच साल में एसीबी और ईओडब्लू ने पांच कार्रवाइयां नहीं की।

एक ही दिन में कई ट्रैप

17 मई को भी एसीबी ने अलग-अलग जिलों में चार कार्रवाई करते हुए पांच भ्रष्ट अफसर व कर्मियों को पकड़ा है। एसीबी की कार्यवाही की शुरुआत कोंडागांव जिले से हुई है। कोंडागांव जिले में जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता टीआर मेश्राम के शासकीय बंगले में एसीबी की टीम ने छापामार कार्यवाही की है। कार्यपालन अभियंता द्वारा विभाग में सप्लीमेंट्री कार्य के एवज में 50 हजार रुपए की रिश्वत ठेकेदार तुषार देवांगन से मांग रहे थे। ठेकेदार की शिकायत के बाद एसीबी ने पहले पुष्टि की फिर आज सुबह-सुबह कार्यपालन अभियंता के शासकीय निवास में 50 हजार रुपए कैश रिश्वत लेते कार्यपालन अभियंता को गिरफ्तार किया है।

एसीबी की दूसरी कार्यवाही बिलासपुर जिले में हुई है। बिलासपुर के तहसील कार्यालय में पदस्थ राजस्व निरीक्षक संतोष देवांगन ने बिलासपुर के तोरवा के रहने वाले प्रवीण कुमार तरुण से तोरवा में स्थित उनकी जमीन के सीमांकन हेतु ढाई लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। जिसकी प्रथम किश्त के रूप में एक लाख रुपए लेकर आज तहसील कार्यालय में बुलाया था। प्रार्थी प्रवीण कुमार तरुण ने इसकी शिकायत बिलासपुर एंटी करप्शन ब्यूरो को की थी। शिकायत के सत्यापन के बाद सुनियोजित ट्रैप कार्यवाही कर तहसील कार्यालय बिलासपुर से राजस्व निरीक्षक संतोष कुमार देवांगन को 1 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एंटी करप्शन ब्यूरो की तीसरी कार्यवाही रायगढ़ जिले के घरघोड़ा में हुई है। झाड़फूंक करने वाले जगमोहन मांझी ग्राम कुर्मी भवना का रहने वाला है। झाड़फूंक से वापस लौटते समय उसे घरघोड़ा रेंज के डिप्टी रेंजर मिलन भगत ने पड़कर जंगली मुर्गा मारने के केस में जेल भेजने का डर दिखाकर 8 हजार रुपए मांगा था। 3 हजार रुपए तत्काल ले लिए थे। 5 हजार की दूसरी किश्त लेते हुए आज एंटी करप्शन ब्यूरो ने डिप्टी रेंजर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

एंटी करप्शन ब्यूरो की चौथी कार्यवाही अंबिकापुर जिले में हुई है। यहां पदस्थ नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के सहायक संचालक (सर्वे) बालकृष्ण चौहान एवं सहायक मानचित्रकार नीलेश्वर कुमार ध्रुव ने ग्राम मोमिनपुर निवासी मोहम्मद वसीम बारी के समधी से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु 35 हजार रुपए के रिश्वत की मांग की थी। पीड़ित मोहम्मद वसीम बारी ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो अंबिकापुर के कार्यालय में की थी। शिकायत सत्यापन के पश्चात आज ट्रैप कार्यवाही की गई तथा नगर एवं ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय अंबिकापुर में सहायक संचालक बालकृष्ण चौहान और सहायक मानचित्रकार नीलेश्वर कुमार ध्रुव को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया

अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन पर करें कड़ी कार्रवाई - जायसवाल

बलौदाबाजार जिले के प्रभारी मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने ली विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक

बलौदाबाजार। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री एवं बलौदाबाजार जिले के प्रभारी मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय बलौदाबाजार स्थित सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन तथा लंबित प्रकरणों के सम्बन्ध में विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण के मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

प्रभारी मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि जिन क्षेत्रों में रेत खदान नही है उन क्षेत्रों के लोगों को अपने निजी उपयोग के लिए ट्रैक्टर में रेत ले जाने में प्रतिबंधित न किया जाय, लेकिन रेत खदान से व्यवसायिक रूप से अवैध तरीके से उत्खनन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करें। अवैध रेत उत्खनन में लगे चैन माउंटेन एवं परिवहन कर रहे वाहनों पर जब्ती की कार्यवाही करें।

उन्होंने आगामी बारिश में मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए पूर्व तैयारी सुनिश्चित करने तथा बाढ़ प्रभावित गांवो में दवाई एवं अन्य प्राथमिक ईलाज की सुविधाएँ व्यवस्थित करने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिए। मलेरिया एवं सिकल सेल की नियमित जांच एवं मलेरिया प्रभावित गांवो में मेडिकेटेड मच्छरदानी का वितरण कराने कहा। बारिश में शहरों में जल भराव की स्थिति निर्मित न हो इसके लिए नालियों की साफ -सफाई तेजी से कराने के भी निर्देश दिए।

मछली पालन को बढ़ावा देने चलेगा जल से आजीविका अभियान

प्रभारी मंत्री ने वृहद स्तर पर किसानों को मछली पालन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु जिले में जल से आजीविका अभियान शुरू करने कहा। उन्होंने कहा की मछली पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें बहुत ही सीमित संसाधन और कम समय में अधिक फायदा लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की प्राथमिकता किसानों, युवाओं और महिलाओं को रोजगार -स्वरोजगार से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करना है।

तोखन साहू, पंच से शुरू किया राजनीतिक करियर, अब बने केंद्रीय राज्यमंत्री

बिलासपुर। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री की शपथ लेने वाले छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से सांसद तोखन साहू पहली बार लोकसभा चुनाव जीतने के बाद संसद पहुंचे हैं। तोखन साहू ने साल 2024 के लोकसभा के चुनाव में बिलासपुर में कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव को बड़े अंतर से हराया? है। साहू समाज से ताल्लुक रखने वाले तोखन साहू को मोदी कैबिनेट में जगह मिली है।

मुंगेली जिले के डिंडोरी गांव में 15 अक्टूबर 1969 को जन्मे तोखन साहू की शिक्षा की बात करें तो उनके पास एम.कॉम की डिग्री है. उनके परिवार में पत्नी लीलावती साहू, एक बेटी और एक बेटा है. तोखन साहू के राजनीतिक करियर की बात करें इसकी शुरुआत 1994 में हुई. जब वे लोरमी ब्लॉक के सूरजपुरा गांव के पंच चुने गए. इसके बाद वे भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और महिला एवं बाल कल्याण समिति के सदस्य सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं.

साहू 2015 में छत्तीसगढ़ में संसदीय सचिव भी थे.इसके बाद 2018 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के धर्मजीत सिंह के सामने हार का भी सामना करना पड़ा. हालांकि, 2024 के चुनाव में पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और उन्होंने शानदार जीत हासिल की.

पहली बार संसद पहुंचे तोखन साहू को केंद्रीय मंत्री बनाया गया है। बिलासपुर संभाग से अपने राजनीति की शुरुआत करने वाले तोखन साहू पहली साल 1994 में सूरजपुरा गांव से पहली बार पंच बने थे। फिर तोखन सरपंच बने। इसके बाद जनपद सदस्य रहने के बाद साल 2013 के विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने तोखन साहू को लोरमी विधानसभा सीट से चुनाव के मैदान में उतारा था। इस चुनाव में लोरमी सीट से तोखन साहू चुनाव जीतने के बाद विधानसभा पहुंचे इसके बाद साल 2015 में विधायक रहते हुए उन्हें मुख्यमंत्री रमन सिंह के कार्यकाल के दौरान संसदीय सचिव नियुक्त किया गया था। बता दे कि हाल ही में छत्तीसगढ़ भाजपा के किसान मोर्चा का? तोखन साहू को प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया था। वही साल 2024 को लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार तोखन साहू को चुनाव के मैदान में उतारा और तोखन साहू चुनाव जीतकर पहली? बार संसद पहुंचे। जहां उन्हें मोदी? सरकार का मंत्री भी बना दिया गया है।

किसान परिवार से आते हैं तोखन

छत्तीसगढ़ के जिला मुंगेली से? आने वाले तोखन साहू ग्राम डिंडौरी लोरमी से आते हैं। तोखन साहू का जन्म 15 अक्टूबर 1969 को हुआ। वह बेहद ही साधारण किसान परिवार से आते? हैं। इनके पिता का नाम बलदाउ प्रसाद साहू है। तोखन ने एमकॉम की? पढ़ाई की है?। तोखन साहू का विवाह लीलावती साहू से हुआ, आज उनका एक बेटा और एक? बेटी है। तोखन वर्ष 2013 में पहली बार लोरमी विधानसभा सीट से विधायक निर्वाचित हुए थे। रमन सिंह सरकार में तोखन साहू को संसदीय सचिव भी बनाया गया था। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में तोखन साहू ने कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव को लगभग 1 लाख 64 हजार से भी अधिक वोटों के अंतर से हराया तो उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया जा रहा है।

क्यों अचानक लग गई मंत्री बनने की लॉटरी

बिलासपुर से सांसद तोखन साहू मंत्री बन गए, शपथ भी हो गई। लेकिन हर किसी के जहन में यह सवाल जरूर है कि तोखन साहू को मंत्री क्यों बनाया गया? जबकि प्रदेश से सीनियर नेता भी सांसद बने हैं। इसके जवाब के लिए समीकरण समझना होगा। खबरों के अनुसार छत्तीसगढ़ की लगभग 1 करोड़ 35 लाख ओबीसी आबादी में साहू समाज का दबदबा सबसे ज्यादा माना जाता है। इसके बाद यादव समाज जो कि करीब 18 प्रतिशत होने का दावा करते हैं। वहीं, कुर्मी समाज की आबादी 6-7 फीसदी है। विधानसभा और लोकसभा को लेकर यह माना जाता है कि साहू समाज ने पिछले 2 दशकों में बीजेपी को ज्यादा समर्थन दिया है। साथ ही परंपरागत रूप से भाजपा को वोट दिया है। इसके पीछे की वजह यही मानी गई है कि भाजपा ने कांग्रेस की तुलना में समाज से अधिक उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं, ज्यादा से ज्यादा मौका देने की कोशिश की।

इसलिए बनाया गया हैं मंत्री

सियासी गलियारों में चर्चा यही है कि साहू समाज को साधने के लिए ही तोखन साहू को मंत्री बनाया गया है। बात 2014 की हो तो साहू समाज से कुल 3 सांसद रहे हैं। जिसमें से बीजेपी से 2 और कांग्रेस से एक सांसद थे। 2019 में यह संख्या घटकर 2 रह गई। भाजपा से जुड़े दोनों सांसद बिलासपुर और महासमुंद लोकसभा सीटों से जीतकर आए थे। अगर बात 2018 के विधानसभा चुनाव की करें तो दोनों पार्टियों ने 22 साहू कैंडिडेट्स को टिकट दिया था। हालांकि बताया जा रहा है कि इस बार साहू समाज ने भाजपा से 2 उम्मीदवारों को मैदान में उतारना की मांग की, लेकिन पार्टी ने इनकार कर दिया। राजनीतिक विशेषज्ञ ने बताया कि बिलासपुर से केवल एक तोखन साहू को मैदान में उतारने से भाजपा के खिलाफ गुस्सा बढ़ गया, यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समाज तक पहुंचे और धमतरी में अपने एक भाषण में उन्होंने दावा किया कि वह भी साहू समाज से हैं।

योग आयोग के माध्यम से प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को योग से जोड़ने के लिए करेंगे कामः साय

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय दसवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने हजारों लोगों के साथ सामूहिक योग किया और स्वस्थ जीवन-शैली के लिए नियमित योगाभ्यास करने का संदेश लोगों को दिया।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह देखकर प्रसन्नता होती है कि जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया जाता है, वह उद्देश्य आज सफल हो रहा है। उन्होंने कहा कि योग का प्रचार और प्रसार आज पूरी दुनिया में हो रहा है। भारत में भी इसे लेकर अद्भुत जागरूकता आई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जो उत्साह आज यहां पर नजर आ रहा है, वैसा ही उत्साह प्रदेश के सभी जिले, ब्लाक और गांवों में भी है। हमारे प्रधानमंत्री

नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ को 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का सुझाव दिया था, जिसके परिणामस्वरूप ही पूरे विश्व में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि योग का अर्थ होता है जोड़ना। योग की प्राचीन परंपरा हम सभी को स्वस्थ जीवन पद्धति से जोड़ती है। योग हमारे मन और मस्तिष्क को आपस में जोड़ता है। योग की प्रक्रिया हमें आध्यात्म और उच्च जीवन मूल्यों से भी जोड़ती है। उन्होंने कहा कि लोग स्व-स्फूर्त योग करने के लिए साइंस कॉलेज मैदान पहुंचे और सामुहिक योग में शामिल हुए। श्री साय ने कहा कि व्यक्ति से ही समाज का निर्माण होता है। योग केवल स्वस्थ जीवन के लिए ही नहीं, बल्कि स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए भी जरूरी है। आज पूरी दुनिया योग के महत्व को समझ रही है और अपना रही है। हमारी सरकार योग आयोग के माध्यम से प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को योग से जोड़ने के लिए लगातार काम करेगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम में उपस्थित विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे तो आपका विद्यार्थी-जीवन संवर जाएगा। योग से एकाग्रता आती है और याददाश्त बढ़ती है। निश्चित रूप से आपको इसका बड़ा लाभ मिलेगा। योग कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देता है। यह तनाव को दूर करता है। जब हम सकारात्मक रहते हुए प्रसन्न भाव से काम करते हैं तो इसका सकारात्मक प्रभाव हमारी कार्यक्षमता में पड़ता है और हमारी छवि अच्छी बनती है, हमारा कैरियर भी संवरता है।

महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कहा कि आज का यह दिन हम सबके लिए गौरव का दिन, स्वाभिमान का दिन है और उल्लास व खुशी का दिन है। आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं और यह तभी संभव हो पाया है जब देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के भगीरथ प्रयास से सर्वे भवन्तु सुखिन:, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दु:खभाग् भवेत् और वसुधैव कुटुंबकम के भाव को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने पर सहमति दी है। योग कसरत ही नहीं जीवन जीने का तरीका है। योग जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। योग जीवन दर्शन है, योग कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ देश और स्वस्थ विश्व के निर्माण के लिए योग को आवश्यक बताते हुए कहा कि योग को जीवन का आधार बनाएं। योग में शरीर मन और आत्मा को जोड़ने का विधान है।

विपरीत हालातों में भी ज्योत्सना के सिर बांधा जीत का सेहरा

कोरबा का गड्ढा तानाखार ने पाटा, मरवाही-रामपुर ने भी साथ दिया

कोरबा। लोकसभा 2024 के इस चुनाव में नेता प्रतिपक्ष वन मैन शो की तरह उभरे हैं। विपरीत हालातों और पार्टीगत झंझावतों से जूझते हुए पत्नी के सिर आखिर जीत का सेहरा सजवा ही दिया। महंत दंपत्ति जनता, कार्यकर्ताओ का आभार जताते नहीं थक रहे।

यह चुनाव एक ऐसे दौर में हुआ जब एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर लोगों के सिर चढ़कर बोल रही है और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। निश्चित तौर पर सत्तारूढ़ पार्टी के प्रति रुझान तब ज्यादा बढ़ जाता है जब अपनी ही पार्टी में नाराजगी बढ़ी हो। 5 वर्षों तक कोरबा लोकसभा की सांसद रहीं ज्योत्स्ना महंत के भी लगभग 2 साल वैश्विक कोरोना काल में चले जाने के बाद काम करने के लिए, लोगों से मिलने के लिए काफी कम वक्त मिला। ज्योत्सना महंत ने अपने प्रतिनिधि के तौर पर जिन्हें जिम्मेदारियां सौंपी, उनमें से कई ने दायित्व का निर्वहन जन भावनाओं के अनुरूप नहीं किया। विधानसभा चुनाव में इसके कारण नाराजगी देखने को मिली क्योंकि उनकी दखल चुनाव में थी। इसके बाद लोकसभा चुनाव में भी यह नाराजगी दिखती रही। भाजपा ने लापता सांसद का हल्ला मचाकर माहौल को और विपरीत करने का काम किया। इधर सत्तारूढ़ दल के प्रति आकर्षण बढ़ा और कईयों ने नाराजगी तो कई ने मजबूरी के कारण सत्ता दल का दामन थामा।

चुनाव में ऐसे कूटनीतिक हालात अप्रत्यक्ष निर्मित किए गए कि कई लोग कांग्रेस का साथ छोड़ गए जिनमें बहुत तो पुराने लोग भी थे और इस चुनाव में उनसे खासी मदद मिल पाती।

भाजपा उम्मीदवार और उनके लोगों ने अपना काम किया लेकिन इन झंझावतों के बीच ज्योत्सना महंत भीतरघात व खुलाघात को जानते हुए भी बिना विचलित हुए डटी रहीं तो उनके साथ कदम से कदम मिलाकर पति डॉ. चरण दास महंत ने मोर्चा संभाला।

एक तरफ जहां भाजपा का बहुत बड़ा ताम झाम राज्य से लेकर राष्ट्रीय स्तर के मंत्री गण और अमला लग रहा तो दूसरी तरफ डॉ.महंत ने अपने राजनीतिक संबंधों और पिता से मिली विरासत को आगे बढ़ाने के लिए जनता के सामने खुद को समर्पित कर दिया। वह लोगों के बीच खुद जाकर मिले। यह फायदा जरूर हुआ कि जो लोग कांग्रेस छोड़कर चले गए, तो उनके कारण डॉ.महंत व आम लोगों के बीच बनती जा रही दूरियां खत्म हो गईं। डॉ. महंत सीधे लोगों के बीच पहुंचे तो आत्मीयता और बढ़ गई।इसका सीधा-सीधा लाभ देखने को मिला और स्थानीय जनप्रतिनिधि ज्योत्सना महंत ने रिकार्ड मतों से जीत हासिल की।

फिर तारणहार बना तानाखार

विपरीत हालातों के बीच कांग्रेस के लिए एक बार फिर पाली तानाखार विधानसभा तारणहार साबित हुआ है। कोरबा जिले का रामपुर विधानसभा और जीपीएम जिले का मरवाही विधानसभा ने भी काफी साथ दिया और यहां के मतदाताओं ने कांग्रेस की झोली में भर-भर कर वोट डाले। सभी क्षेत्र में जहां खासकर कोरबा और कटघोरा विधानसभा के शहरी इलाकों में भाजपा की लहर चली और नाराजगी के कारण कांग्रेस के अधिकांश नेताओं ने खुलकर अपने प्रत्याशी के लिए काम नहीं किया जिससे इस चुनाव में कोरबा विधानसभा में काफी बड़ा अंतर नजर आया तो कटघोरा में भी कुछ खास बढ़त कांग्रेस को नहीं मिली। यदि कटघोरा के कांग्रेसी साथ देते तो मतों का अंतर कहीं ज्यादा होता। दूसरी तरफ कोरबा में कांग्रेसियों की नाराजगी दूर नहीं की जा सकी, यह बात डॉ. महंत भली भांति जानते थे। उन्होंने सबको एक करने की कोशिश की। डॉ. महंत ने जयचन्दो की करतूतों और फूल छाप कांग्रेसियों की शैली को समझने के साथ-साथ अंदरूनी तौर पर अपनी तैयारी जारी रखी। डॉ.महंत की कुशल रणनीति ने विपक्ष को आखिरकार शिकस्त दे ही दी। अब उनके वन मैन शो बन जाने की चर्चा लोकसभा ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में हो रही है।

मुख्यमंत्री साय सहित मंत्रिगणों ने सांसद बनने पर बृजमोहन अग्रवाल को किया सम्मानित

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में यहां महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री एवं नवनिर्वाचित सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री श्री साय ने श्री बृजमोहन अग्रवाल को शाल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने श्री अग्रवाल को सांसद निर्वाचित होने पर बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि श्री बृजमोहन अग्रवाल देश में सर्वाधिक वोटों से जीतने वाले सांसदों में शामिल हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस अवसर पर मंत्री श्री अग्रवाल द्वारा छत्तीसगढ़ के विकास के लिए किए गए कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा की वे सतत रूप से आम जनता की सेवा करते आ रहे हैं। जनता ने उन्हें ढेर सारा प्यार दिया है। इस बार उन्होंने रिकार्ड मतों से विधानसभा और लोकसभा चुनाव जीतकर जनता के बीच अपनी लोकप्रियता साबित की है।

उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव और श्री विजय शर्मा सहित मंत्री परिषद के सदस्यों ने श्री अग्रवाल को सम्मानित किया। श्री बृजमोहन अग्रवाल ने इस अवसर पर कहा कि आप लोगों के साथ मेरा हमेशा आत्मीय और अटूट रिश्ता रहेगा। उन्होंने सम्मान के लिए सभी के प्रति आभार प्रकट किया।

बृजमोहन अग्रवाल ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा

छत्तीसगढ़ में भाजपा के सीनियर नेता बृजमोहन अग्रवाल ने बुधवार को विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के बाद अग्रवाल ने दो दिनों पहले विधायक पद से इस्तीफा दिया था। अग्रवाल (64) ने सोमवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था। हाल में हुए लोकसभा चुनाव में अग्रवाल ने रायपुर सीट पर कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय को 5 लाख75 हजार 285 मतों से हराया था। अग्रवाल ने नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को अपना इस्तीफा सौंपा। अग्रवाल राज्य में स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, संसदीय कार्य, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व तथा पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के मंत्री थे।

आठ बार विधायक रह चुके अग्रवाल ने पिछले साल विधानसभा चुनाव में रायपुर शहर दक्षिण विधानसभा सीट पर कांग्रेस के अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ सबसे अधिक 67,719 मतों के अंतर से जीत दर्ज की थी। अग्रवाल राज्य में भाजपा के प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद 'पीटीआई-वीडियो' से बातचीत में अग्रवाल ने बताया कि बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की अंतिम बैठक में भाग लेने के बाद उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।

मंत्री पद त्यागने के साथ हुए भावुक

अग्रवाल ने कहा कि मैं 35 साल तक विधायक रहा। मैंने अविभाजित मध्य प्रदेश में तीन साल और छत्तीसगढ़ में 16 साल मंत्री के रूप में लोगों की सेवा की। मैं अधिकारियों, कर्मचारियों, विधायकों और उन सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मेरे साथ काम किया और मेरा समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यदि मेरे कार्यकाल के दौरान किसी को मेरी वजह से ठेस पहुंची है तो मैं क्षमा चाहता हूं।

श्रमिकों को किफायती दर पर मिलेगा भोजन

मुख्यमंत्री की पहल पर रायपुर, कोरबा और कुनकुरी में मॉडल श्रम अन्न केन्द्र शुरू होंगे

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार श्रमिकों के लिए नये-नये फैसलें ले रही हैं। कामकाजी श्रमिकों की दिक्कत को महसूस करते हुए उन्हें उनके कार्य स्थल के पास किफायती दर पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए मॉडल श्रम अन्न केन्द्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। यह केन्द्र रायपुर, कोरबा और कुनकुरी में खुलेंगे।

श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि मॉडल श्रम अन्न केन्द्र रायपुर के तेलीबांधा, कोरबा के नगर निगम बुधवारी टंकी और कुनकुरी में स्थापित किए जाएंगे। वर्तमान में 9 जिलों में 24 जगहों पर श्रम अन्न केंद्र संचालित हो रहे हैं। योजना का विस्तार करते हुए 13 जिलों के 27 स्थानों पर नवीन श्रम अन्न केंद्र शुरु किए जाएंगे। बैठक आज मंगलवार को नवा रायपुर स्थित मंडल कार्यालय में श्रमायुक्त एवं सह-सचिव श्रीमती अलरमेल मंगई डी, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मण्डल की सचिव श्रीमती सविता मिश्रा, अपर श्रमायुक्त श्री एस.एल. जांगडे सहित श्रम विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

श्रम मंत्री श्री देवांगन ने श्रम विभाग के मण्डलों में असंगठित एवं निर्माण श्रमिकों के पंजीयन, योजनाओं के आवेदनों के निराकरण में श्रमिकों अभिलेखों का सुस्पष्ट मिलान कर शत् प्रतिशत पात्र श्रमिकों को लाभ प्रदाय करना सुनिश्चित करें। साथ ही ऐसे श्रमिक जिनके अभिलेख में कमी, त्रुटि पाई जाती है उन श्रमिकों से अभिलेख पूर्ण कराकर पंजीयन, योजना का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। खैरागढ़ जिले के अंतर्गत निर्माण, असंगठित श्रमिकों के पंजीयन, योजना आवेदनों में स्वघोषणा प्रमाण पत्र को अमान्य कर जिले द्वारा निरस्त किये गये आवेदनों को पुन: जांच करने के निर्देश दिये गये।

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में कुल 6,386 कारखानें हैं, जिसमें 922 जोखिम श्रेणी के कारखानें के रूप में चिन्हित किए गए हैं। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए प्रदेश में नि:शुल्क कोचिंग सहायता योजना संचालित की जा रही है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक- गुलाब दास दीवान, द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि. (छ.ग.) भवन, प्रेस काम्पलेक्स रजबंधा मैदान रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित एवं ग्राम-पोस्ट-पवनी, तहसील-बिलाईगढ़, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.), 493338 से प्रकाशित। RNI NO. CHHHIN/2022/83778 सम्पादक- गुलाब दास दीवान, मो. 9294743139